रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1971 (पौष 12, 1892)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1971 (PAUSA 12, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 20 अक्तूबर 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 20th October 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

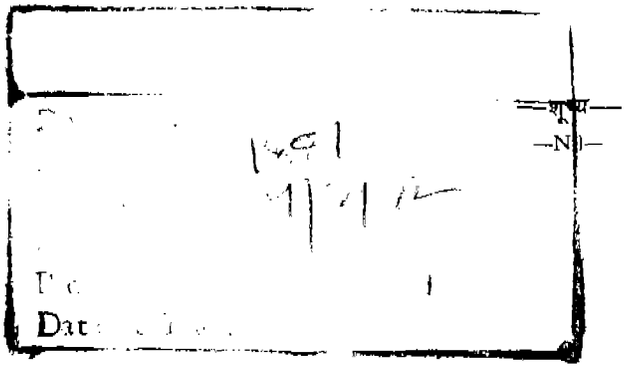

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	1
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	1
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	
पूरक संख्या 1—	
26 दिसम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	—
5 दिसम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	11

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	1
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	1
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	1
SUPPLEMENT NO. 1	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 26th December 1970	1
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 5th December, 1970	11

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 1970

सं० 62-प्रेज/70—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं ।

अधिकारी का नाम और पद

श्री चुक्कपल्ली वेंकटेश्वर राव,
पुलिस निरीक्षक
जिला गुंटूर,
आन्ध्र प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

17 और 19 मई, 1969 के बीच गुंटूर जिले में भयंकर तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, पेड़ उखड़ गये, बिजली की व्यवस्था टूट गई और सड़क व रेल यातायात भंग हो गया । 19 मई, 1969 को दिन के लगभग 2 बजे श्री चुक्कपल्ली वेंकटेश्वर राव को सूचना मिली कि गांव कुलुला के निवासियों की हालत संकटपूर्ण है क्योंकि बहुत से निवासी बाढ़ में बह गये और शेष निस्सहाय अवस्था में वृक्षों और मकानों की छतों पर लटके हुए हैं । श्री वेंकटेश्वर राव मछेरों से एक दो नावें लेने के लिये तटवर्ती एक गांव की ओर गये किन्तु उस स्थान तक पहुंच न पाये क्योंकि रास्ते में कुन्देरू नहर को पार करना था और उसमें बाढ़ आई हुई थी । तब श्री राव ने एक प्राइवेट लारी ली और मुत्तायपालम की ओर रवाना हो गये । वहां उन्होंने मछुये की एक नाव ली और बड़ी मुश्किल से एक मछुये को तैयार किया जो श्री राव को नाव में चिराला तक ले तो आया पर बाढ़ की भीषणता के कारण उसने नाव को और आगे ले जाने से इन्कार कर दिया । तब श्री राव ने स्वयं अपने आप को भारी खतरे में डालकर नाव को खेया । नाव को चार घंटे तक चलाने के बाद वे उस गांव में पहुंचे और आधी रात में छः स्त्रियों/लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर ले आये । दूसरे दिन प्रातः उन्होंने दो मछुओं की सहायता से और 150 व्यक्तियों को बचाया तथा उनके प्राथमिकता उपचार व खाने-पीने का प्रबन्ध किया ।

श्री चुक्कपल्ली वेंकटेश्वर राव ने अपने जीवन को भारी खतरे में डालते हुए असहाय स्त्री-पुरूषों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस एवं पहल-कदमी का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 मई 1969 से दिया जायेगा ।

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1970

नियम

सं० 6/49/70-सी० एस० (I)—निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1967 के नियम 5 तथा भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं में श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के पदों में रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1969 के नियम 4 में विहित उपबन्धों के अनुसरण में (1) निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों, जो 1 नवम्बर 1962 के बाद सशस्त्र सेना में नियुक्त किये गये थे, तथा (2) भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित क्रमशः वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के अन्तर्गत उल्लिखित सेवा/पदों में उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये उनके प्रवरण के लिये 1971 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित किये जा रहे हैं । पूर्वोक्त नियुक्त आपातकालीन आयुक्त तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1967 तथा भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवाओं में श्रेणी III तथा श्रेणी 4 के पदों में रिक्त स्थानों का आरक्षण) नियम, 1969, यदि सरकार द्वारा इन्हें बढ़ाया न जायें, तो क्रमशः 29 जनवरी 1971 तथा 1 जुलाई 1971 को और इन तारीखों के बाद भी समाप्त हो जायेंगे ।

वर्ग 1

श्रेणी II की सेवाएं/पद

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड

(ii) भारतीय विदेश सेवा (ख) में सहायक का सामा काडर ग्रेड

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक ग्रे और

(iv) पर्यटन विभाग/संसदीय कार्य विभाग/भारत का चुनाव आयोग, तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलिति न होने वाले केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य विभागों में विद्यमान सहायकों के पद ।

वर्ग 2

श्रेणी III की सेवाएं/पद

(i) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड 1 (सहायक), और

(ii) अनुसंधान, रूपरेखा तथा मानक संगठन के महा-निदेशालय, लखनऊ तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सम्मिलिति न होने वाले केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य विभागों में विद्यमान सहायकों के पद ।

नियम 2 के उपबन्धों के अधीन कोई उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगी हो सकता है । उम्मीदवार जिन सेवाओं/पदों के बारे में वह चाहता है कि उस पर विचार किया जाये, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर दें ।

टिप्पणी उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जितनी सेवाओं/पदों के लिये वे चाहते हैं कि उन पर विचार किया जाये उनके अधिमान क्रमों का अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें । उनको यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे जिन सेवाओं/पदों को चाहते हैं उनका भी उल्लेख करें, ताकि योग्यता-क्रम से उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनके अधिमान पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र में सेवाओं/पदों के लिये जिस अधिमान क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है उसमें कोई बात जोड़ने या परिवर्तन करने के उस अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जो 31 दिसम्बर 1971 को या इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुंचे ।

2. (क) आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी केवल वर्ग 1 में उल्लिखित श्रेणी II के सेवाओं पदों में सहायकों के पदों में उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक केवल वर्ग II में उल्लिखित श्रेणी III के सेवाओं/पदों में सहायकों के पदों में उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार होगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये उतने रिक्त स्थान आरक्षित किये जायेंगे जितने भारत सरकार निर्धारित करें ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से अभिप्राय नमांकित में उल्लिखित जाति/आदिम जाति में से किसी एक से है; .म्बई पुर्नगठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 तथा संविधान अनुसूचित आदिम जाति (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951 संविधान (जम्मू तथा काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन व दियू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन व दयू) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 ।

4. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

5. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन व आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो 1 नवम्बर 1962 के बाद सशस्त्र सेना में, आयुक्त हुए थे तथा जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पूर्व निर्मुक्त किये गये हों या उसके बाद 1971 की समाप्ति तक निर्मुक्त कर दिये जायेंगे, इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी : इन नियमों के लिये "निर्मुक्त" से अभिप्राय निम्नलिखित होगा :

(i) निर्मुक्त के नियत वर्ष के अनुसार निर्मुक्त करना,

(ii) किन्तु यह वास्तविक निर्मुक्त सशस्त्र सेनाओं में कुछ समय तक सेवा कर लेने के बाद हुई हो, प्रशिक्षण के अन्त में उसके दौरान, अथवा वास्तविक सेवा में लिये जाने के पूर्व प्रशिक्षण काल के लिये दिये गये अल्पकालीन सेवा कमीशन के अन्त में या उसके दौरान नहीं, वास्तविक निर्मुक्त के अन्तर्गत दुर्व्यवहार या अकुशलता के कारण या अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त हुए अधिकारियों के मामलें भी नहीं आते ।

टिप्पणी-2 :—"निर्मुक्त का नियत वर्ष" अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(i) जहां तक इस का सम्बन्ध आपात कमीशन अधिकारियों से है वह वर्ष जिसमें भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार जिस वर्ष में निर्मुक्त किये जाने वाले हैं, और

(ii) जहां तक इसका संबन्ध अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों से है, जिस वर्ष अल्प कालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के रूप में 5 वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होने वाली है ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Departments of Petroleum and Chemicals)

New Delhi, the 23rd January 1971

No. A-32011/1/70-*Adm.I.*—In supersession of this Ministry Notification of even No. dated 16-1-1971. The President is pleased to appoint the undermentioned permanent officers of Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the Service with effect from the dates mentioned against each or until further orders whichever is earlier :—

1. Shri R. N. Chopra—From 1-1-1971 to 8-2-1971 and 10-2-1971 to 28-2-1971.
2. Shri N. Srinivasan—From 1-1-1971 to 28-2-1971.

2. The President is also pleased to appoint Shri R. N. Chopra and Shri N. Srinivasan, the permanent officers of the Section Officers' Grade as Under Secretary in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Departments of Petroleum and Chemicals) for the aforesaid periods.

A. J. F. D'SOUZA, Dy. Secy.

(Department of Mines and Metals)

Geological Survey of India

Calcutta-13, the 5th February 1971

No. 2339(*BS*)/19*B*.—The President is pleased to appoint Shri B. Subrahmanyam, Geophysicist (Jr.), Geological Survey of India, as Geophysicist (Senior) in the same department in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30th November, 1970, until further orders.

M. S. BALASUNDARAM, Director General

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 13th January 1971

No. E.I(*G*)(*K*-84).—Shri K. P. Banerjee relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) with effect from the 31st December, 1970 (afternoon).

2. The Services of Shri K. P. Banerjee are placed at the disposal of the Commission of Inquiry on Large Industrial Houses with effect from the 1st January, 1971 (forenoon).

No. A-12022/10/70-*E.I.*—In continuation of this Department Notification of even number dated the 19th November 1970, the President is pleased to allow Shri R. C. Sethi, a permanent Grade I officer of the Central Secretariat Service to continue to officiate the Selection Grade of the Service for a further period from 29th November, 1970 to 11th December, 1970 (both days inclusive).

2. The President is also pleased to allow Shri R. C. Sethi to continue to officiate as Deputy Secretary in the Department of Industrial Development for the aforesaid period.

The 19th January 1971

No. A-12023/2/70-*E.I*—The President is pleased to appoint the following officers permanent in Grade IV of the Central Secretariat Service to officiate as Section Officers in the Department/Office for the period shown below against each :—

S. No.	Name	From	To	Name of the Department/ Office
1.	Shri Yag Paul ..	27-1-71	26-5-71	D.G.T.D.
2.	Shri N.R. Sharma	11-1-71	12-2-71	D.G.T.D.
3.	Miss M.R. Ticlo ..	11-1-71	10-2-71	Deptt. of I.D.
4.	Shri N.N. Puri ..	15-1-71	14-2-71	Deptt. of I.D.

2. The President is pleased to allow Shri P.N. Nayar, an officer permanent in Grade IV of the Central Secretariat Service to continue to officiate as Section Officer in the Department of Industrial Development upto the 5th February, 1971.

G. RAMANATHAN, Under Secy.

Department of Company Affairs

New Delhi-1, the 1st February 1971

No. PFG(111)-*CLA*/60.—In exercise of the pc ferred by clause (a) of sub-section (i) of Section ' Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Gc have appointed Shri C. L. Suri, Superintendent-*cum* ant in the Office of the Official Liquidator, U.P. All officiate as Official Liquidator, High Court, U.P. , in addition to his own duties as Superintenc Accountant with effect from the forenoon of 21st I 1970 until further orders *vice* Shri S. C. Bhardwa leave.

No. PFG(122)-*CLA*/61.—Shri K. Vaitheeswa Liquidator High Court, Madras was granted exte earned leave for 2 days from 25-12-1970 to 2 with permission to suffix Sunday the 27th December the leave.

2. In exercise of the powers conferred by clau sub-section (i) of Section 448 of the Compa (1 of 1956) the Central Government have Rajagopalan, Assistant Official, Liquidator, r as Official Liquidator, High Court, Madras own duties as Assistant Official Liquidator , 30-11-1970 to 26-12-1970 *vice* Shri K. Vaithees leave.

3. In exercise of the powers conferred by clause (sub-section (i) of Section 448 of the Companies Act, 19 (1 of 1956) the Central Government have on his return from leave appointed Shri K. Vaitheeswaran, to officiate as Official Liquidator, High Court, Madras with effect from the forenoon of 28th December, 1970 until further orders *vice* Shri K. Rajagopalan.

No. PFR(48)-*CLA*/62.—Shri S. P. Khanna, Registrar of Companies, Bangalore has been granted earned leave for 36 days from 21-12-1970 to 25-1-1971 with permission to prefix Sunday the 20th December, 1970 and suffix holiday on 26th January, 1971 to the leave.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) read with the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Company Affairs and Insurance) Notification No. 72 dated the 1st January, 1966 the Company Law Board have appointed Shri K. Panchapakesan, Senior Technical Assistant in the Office of the Registrar of Companies, Madras to officiate on a purely temporary and *ad-hoc* basis as Registrar of Companies, Mysore Bangalore, with effect from the afternoon of 19th December, 1970 until further orders *vice* Shri S. P. Khanna granted leave.

No. PFG(172)-*CLA*/64.—Shri P. T. Gaiwani, Official Liquidator, High Court, Delhi has been granted earned leave for 20 days with effect from the 14th December 1970 to 2nd January, 1971 with permission to prefix 12-12-1970 and 13-12-1970 being 2nd Saturday and Sunday and su 3-1-1971 being Sunday to the leave.

2. In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (i) of Section 448 of the Companies Act, 19 (1 of 1956) the Central Government have appointed on purely temporary and *ad-hoc* basis Shri P. C. Kapoor, Senic Technical Assistant of the office of the Official Liquidator High Court Delhi to officiate as Official Liquidator High Court Delhi with effect from the afternoon of 11th December 1970 until further orders *vice* Shri P. T. Gajwani granted leave.

No. PFG(172)*CLA*/64.—In exercise of the powers cor ferred by clause (a) of sub-section (i) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) the Central Govern ment have on his return from leave appointed Shri P. T. Gajwani to officiate as Official Liquidator, High Cou Delhi with effect from the forenoon of 4th January, 197 until further orders *vice* Shri P. C. Kapoor reverted.

No. PFG/273/*Admn II*/70.—On the recommendations of the Union Public Service Commission and in exercise of the powers conferred by sub-section 20 of section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Govern ment of India, Ministry of Finance (Department of Com pany Affairs and Insurance) Notification No. G.S.R. 72 dated the 1st January 1966 the Company Law Board have appointed Shri Probodh to officiate as Assistant Registrar o

anies, West Bengal, Calcutta with effect from the fore-of 11th January, 1971 until further orders *vice* Shri Guha reverted.

S. S. Singh, Under Secy.

:.Y OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 8th December 1970

F. A-25/70-ME(UG).—While proceeding on deputa-broad for higher training in U.S.A. under the Popula-Council Fellowship Programme in the field of Family ng Dr. (Mrs.) Amla Rama Rao, an Officer of the lists Grade of the C.H.S. relinquished the charge of ›st of Lecturer in Preventive and Social Medicine in the Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi, afternoon of the 2nd September, 1970.

P. MUKHOPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 1971

...HE.—The President is pleased to accept ;Shri V. Rajagopalan, Assistant Adviser : Public Health Engineering Organisation, :th, Ministry of Health and Family Plan-Housing and Urban Development from with effect from 14-9-1970 (afternoon).

S. K. SUDHAKAR, Under Secy.

Delhi, the 30th January 1971

No. A.120..(i)-55/70-*CHS.I(Pt.)*.—The President is pleased to appoint Dr. M. P. Shrivastava, an officer of General Duty Officer Grade II to the Specialists' Grade of the Central Health Service and to post him as Lecturer in Medicine in the Maulana Azad Medical College, New Delhi, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of the 5th December, 1970, until further orders.

Dr. M. P. Shrivastava relinquished charge of the post of Junior Medical Officer, Willingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi, on the forenoon of the 5th December, 1970.

On reversion from the post of Lecturer in Medicine, Maulana Azad Medical College, New Delhi, Dr. R. C. Bhasin assumed charge of the post of Physician at the Irwin Hospital New Delhi, on the forenoon of the 5th December, 1970.

Dr. R. C. Bhasin relinquished the charge of the post of Lecturer in Medicine at the Maulana Azad Medical College, New Delhi, on the forenoon of the 5th December, 1970.

Dr. (Miss) Shiela Rao relinquished charge of the post of Physician at the Irwin Hospital, New Delhi, on the forenoon of the 5th December, 1970.

The 1st February 1971

No. A.24012/14/70-*Estt.(P)*.—In continuation of this Department's notification No. A.24012/14/70-Estt.(P), dated the 3rd December, 1970, the President is pleased to appoint Shri P. C. Arora, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service, to officiate in Grade I of the Service for the following further periods :—

From 1-1-71 to 30-1-71—30 days.
From 1-2-71 to 2-3-71—30 days.

2. The President is also pleased to appoint Shri P. C. Arora s Under Secretary in the Department of Health for the afore-said period.

The 2nd February 1971

No. A.39012/6/70-*CHS.I*.—Consequent on the acceptance of her resignation, Dr. (Kumari) Asha Tewari, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service (on an *ad-hoc* basis) relinquished charge of the post of Obstetrician and Gynaecologist, Safdarjang Hospital, New Delhi on the afternoon of the 1st January, 1971.

No. F. 3(*IV*)-2/69-*CHS.I*.—Consequent upon her transfer Dr. (Kumari) Soibam Subadani Devi, an officer of the General Duty Officer, Grade I of the Central Health Service assumed charge of the post of Junior Pathologist in the General Duty Officer Grade I of the Central Health Service, Swami Dayanand Hospital, under the Delhi Municipal Corporation, Delhi with effect from 12th January, 1971 (Forenoon).

No. A.12026/54/70-*CHS.I*.—On his reversion, Dr. A. K. Mitra, an officer of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service relinquished charge of the post of Deputy Serologist and Chemical Examiner to the Government of India at Calcutta on the afternoon of the 30th November, 1970 and assumed charge of the post of Assistant Serologist and Chemical Examiner to the Government of India at Calcutta on the same day.

No. F. 3(*III*)-57/69-*CHS.I*.—The President is pleased to appoint Dr. V. P. Pathak, an officer of the General Duty Officer Grade I of the Central Health Service to the Specialists' Grade of the Central Health Service and to post him as Assistant Director (Medical), National Malaria Eradication Programme, Lucknow, on an officiating basis, with effect from the forenoon of the 26th December, 1970, until further orders.

2. Dr. Pathak relinquished charge of the post of Deputy Airport Health Officer, Delhi Airport, Palam, on the forenoon of the 18th December, 1970.

No. F. 14-11/67-*CHS.I*.—Consequent on his transfer, Dr. A. Banerjee, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service relinquished charge of the post of Medical Superintendent, Central Hospital, Karma under the Mica Mines Labour Welfare Fund, with effect from the 4th January 1971 (FN).

No. A.22012/2/71-*CHS.I*.—Consequent on her transfer, Dr. (Smt.) M. H. Bhagat, an officer of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service relinquished charge of the post of Family Planning Officer, Central Government Health Scheme, New Delhi on the afternoon of the 17th December, 1970 and assumed charge of the post of Deputy Airport Health Officer, Delhi Airport, Palam, on the forenoon of the 18th December, 1970.

No. A.22012/17/70-*CHS.I*.—Consequent on his transfer, Dr. B. N. Halder, an officer of Supertime Grade II of the Central Health Service relinquished charge of the post of Regional Director (Family Planning and Maternal and Child Health), Bhopal, on the afternoon of the 27th November, 1970 and assumed charge of the post of Assistant Commissioner (Family Planning), Department of Family Planning, on the afternoon of the 30th November, 1970.

No. F. 3(*IV*)-3/68-*CHS.I*.—Consequent on his appointment to General Duty Officer Grade I of the Central Health Service and in the post of Family Planning Officer, Regional Health Office (Family Planning), Chandigarh, Dr. N. N. Biswas, relinquished charge of the post of Medical Officer, Public Health (Sadar), Directorate of Health Services, Agartala on the afternoon of the 4th November, 1970.

No. F. A-400-12/3/70-*CHS.I*.—Consequent on his attaining the age of superannuation, Dr. S. L. Marwaha, an officer of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service relinquished charge of the post of Medical Officer, Central Government Health Scheme, Delhi, on the afternoon of the 31st December, 1970.

No. F. 3(*II*)-7/69-*CHS.I*.—The President is pleased to appoint Dr. Adarsh Singh Mahal, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service and holding the post of Associate Professor of Psychiatry, All India Institute of Mental Health, Bangalore, to Supertime Grade II of the Central Health Service and post him as Professor of Psychiatry, All India Institute of Mental Health, Bangalore, in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 11th January, 1971 until further orders.

The 5th January 1971

No. A.12026/51/70-*CHS.I*.—The President is pleased to appoint Dr. U. C. Rai, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service, to the post of Associate Professor of Physiology, Maulana Azad Medical College, New Delhi, on an *ad-hoc* basis with effect from the 28th August, 1970 (F.N.), until further orders.

2. Dr. U. C. Rai relinquished charge of the post of Assistant Professor of Physiology, Maulana Azad Medical College, New Delhi, on the 28th August, 1970 (F.N.).

No. A.12026/9/70-*CHS.I.*—The President is pleased to appoint Dr. A. R. Aggarwal, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service and presently holding the post of Anaethetist at the Irwin Hospital, New Delhi, to the post of Assistant Professor of Anaesthesiology, at the Maulana Azad Medical College, New Delhi on an *ad-hoc* basis, with effect from the forenoon of the 23rd February, 1970 until further orders.

Dr. A. R. Aggarwal relinquished charge of the post of Anaesthelist at the Irwin Hospital, New Delhi, on the forenoon of the 23rd February, 1970.

The 5th February 1971

No. A.24012/13/70-*Estt.(P)*.—The President is pleased to appoint Shri A. N. Varma, a permanent officer of Grade I of the Central Secretariat Service, as Deputy Secretary in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) with effect from the forenoon of the 30th January, 1971, until further orders.

No. A.38012/3/71-*CHS.I.*—Consequent on attaining the age of superannuation Dr. J. N. Bakaya, an officer of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service relinquished charge of the post of Junior Radiologist, Safdarjang Hospital, New Delhi, on the afternoon of the 4th January, 1971.

No. A.12034/41/70-*CHS.I.*—On his reversion from the Government of Gujarat, Dr. Shiva Datta Nishith, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service assumed charge of the post of Assistant Professor of Physiology at the Himachal Pradesh Medical College, Simla on the afternoon of the 31st December, 1970.

No. F. 3(*II*)-15/68-*CHS.I.*—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sneh Lata Nath, an Officer of the Specialists Grade of the Central Health Service to the Supertime Grade II of the Central Health Service and to post her as Professor of Anaesthesia, Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi, in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 26th November, 1970, until further orders.

No. A-12025(*i*)-12/70-*CHS.I.*—The President is pleased to appoint Dr. V. P. Sood to the Specialists' Grade of the Central Health Service and to post him as Assistant Professor of E.N.T. in the Himachal Pradesh Medical College, Simla in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 30th November, 1970 until further orders.

Dr. V. P. Sood relinquished charge of the post of Assistant Professor of E.N.I. in the Maulana Azad Medical College, New Delhi on the afternoon of the 28th November, 1970.

No. A.12025(*I*)-12/70-*CHS.I.*—On his reversion, Dr. H. C. Bahri, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service, relinquished charge of the post of Assistant Professor of E.N.T. in the Himachal Pradesh Medical College, Simla on the forenoon of the 30th November, 1970 and assumed charge of the post of E.N.T. Specialist, Safdarjang Hospital, New Delhi on the forenoon of the 5th December, 1970.

No. A.12025(*i*)-130/70-*CHS.I.*—Consequent on his appointment as Professor of Pathology and Bacteriology, at the Goa Medical College, Panaji, Dr. P. C. Beohar, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health service, relinquished charge of the post of Associate Professor of Pathology and Bacteriology at the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry on the afternoon of 5th January, 1971.

The 8th February 1971

No. A.22012/10/70-*CHS.I.*—Consequent on his transfer, Dr. R. P. Bhagi, an officer of the Specialists' Grade of the Central Health Service and holding the post of Senior Medical Officer, T.B. Clinic, Motinagar under the Delhi Municipal Corporation assumed charge of the post of T.B. Control Officer, Delhi Municipal Corporation, Delhi with effect from the 7th October, 1970.

R. N. SINHA, Under Secy.

New Delhi-11, the 2nd February 1971

CORRIGENDUM

No. F. 1-4/67-*CHS.II(Pt.)*.—*Read* "Dr. (Smt.) S. Baluja" *instead* of "Dr. (Smt.) S. B. Baluja" occurring in this Ministry's Notification and Order No. F. 1-4/67-CHS.II dated the 21st August, 1967 at Serial Nos. 348 and 361 respectively and at S. No. 422 of Notification No. F. 1(III)-2(B)/64-CHS dated 1-1-1965.

The 5th February 1971

No. F. 1-2/68-*CHS.II.*—In pursuance of Rule 7A(i)(b) of the Central Health Service Rules, 1963, as amended by the Central Health Service (Amendment) Rules, 1966, and of all other powers enabling him in this behalf, the Secretary, Ministry of Health & Family Planning, Works, Housing and Urban Development (Department of Health) is pleased to appoint Dr. Mahesh Prasad Agarwal, Junior Medical Officer, P & T Dispensary, Nagpur, on probation, to the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service with effect from the 9th September, 1966.

No. A.22013/8/70-*CHS.II.*—Consequent on his transfer from the Dandakaranya Project, Dr. R. C. Saha, an officer of the General Duty Officer Grade II of the Central Health Service, assumed charge of the post of Assistant Port Health Officer, Calcutta on the forenoon of the 23-12-1970.

No. F. 9-12/69-*CHS.II.*—Consequent on her transfer under the Coal Mines Labour Welfare Fund, Dr. (Smt.) Ramesh Tewari, an officer of the General Duty Officer Grade II of the Central Health Service, relinquished charge of the post of Junior Medical Officer under the Central Government Health Scheme, New Delhi on the afternoon of the 31-12-1970.

No. F. 14-3/69-*CHS.II.*—In pursuance of rule 8-A of the Central Health Service Rules, 1963, as amended from time to time, and of all other powers enabling him in this behalf, the Secretary, Departments of Health and Family Planning is pleased to appoint Dr. R. P. Atreya, T.B. Officer—redesignated as Junior Medical Officer (T.B.), T.B. Clinic, Simla, in the General Duty Officer, Grade II of the Central Health Service in an officiating capacity with effect from the 1st April 1968.

No. F. 3-14/69-*CHS.II(Pt.)*.—Consequent on the acceptance of her resignation, Dr. (Km.) Asha Mehrotra relinquished charge of the post of Junior Medical Officer, Coal Mines Labour Welfare Fund on the 1st June, 1970 ((FN).

P. V. HARIHARASANKARAN, Under Secy. (CHS)

New Delhi-11, the 5th February 1971

No. A.39013/15/70-*CHS.II.*—The Secret of Health and Family Planning is pleased nation of Dr. Agya Singh—an officer of Officer Grade II of the Central Health quished charge of the post of Junior Medic don Hospital and Nursing Home, New Delh of the 23-12-1970.

P. V. HARIHARASANKARAN

his Board's Telegraphs Telegraph ineering Tele- 71 to ich-

(Department of Works, Housing & U.I

New Delhi, the 30th January 1971

No. A.12023/34/70-*Adm-I.*—The President is plee to appoint Shri A. K. Narang, a permanent Assistant of t S.S. Cadre of the Deptt. of Works, Housing and Urban opment, presently working in the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery as Junior Analyst in the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery with effect from the forenoon of the 15th January, 1971, until further orders *vice* newly created post.

The 4th February 1971

No. A-22012/1/70-*Admn.I.*—The President is pleased to appoint Shri R. K. Chib, a permanent officer of the Sectio Officer's Grade of the Central Secretariat Service as Deput Director of Estates in the Directorate of Estates with effe from the 14th December, 1970 (FN) to the 16th Janua 1971 (AN).

No. A-22012/1/70-*Admn.I.*—The President is pleased appoint Shri R. K. Chib, a permanent officer of the Secti Officers' grade of the Central Secretariat Service to officia in Grade I of the service with effect from the 4th Januai 1971 (forenoon) to the 4th March, 1971, (afternoon).

2. The President is also pleased to appoint Shri R. K. Ch as Under Secretary, Department of Works, Housing & U. with effect from the 4th January 1971 (forenoon) to the March, 1971 (afternoon).

S. L. VASUDEVA, Under S

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 16th January 1971

No. 32014/1/70-*E.I.*—In partial modification of this Department's Notification of even number dt. 29-12-70, Shri S. N. Lal, an Assistant of the CSS belonging to the cadre of the Department of Agriculture (Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Coopn.) and offg. as Section Officer in the Department of Agriculture, New Delhi, relinquished charge of the post of Section Officer w.e.f. 16-11-70 (AN).

2. The President is pleased to appoint Shri S. N. Lal, a ermanent Assistant of the CSS, belonging to the cadre of the Department of Agriculture (Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Coopn.) as an offg. Section Officer in the Department of Agriculture for the period from 18-11-70 (FN) to 28-2-71 (AN).

The 21st January 1971

No. A.32013/1/70-*Estt.I.*—The President is pleased to oint Shri Raghubir Narain a permanent officer of the Sec- Officers' Grade of the CSS and working as Section Offi- in the Ministry of Food, Agriculture, Community Deve- ment and Cooperation (Department of Agriculture) to iciate in Grade I of the Service for a period of two months .f. the forenoon of the 2nd January 1971, or till a decision the recommendations of the SIU is taken, whichever is rlier.

The President is also pleased to appoint Shri Raghubir arain as Under Secretary in the Indian Council of Agricul- ral Research for the aforesaid period.

No. A-32013/1/70-*Estt.I.*—The President is pleased to oint Shri G. S. Sindhu, a permanent Officer of the Section ers' Grade of the CSS (belonging to the cadre of the artment of Agriculture) to officiate in Grade I of the Ser- for the period from 16th December, 1970 to 15th ary, 1971, or till a decision on the recommendations of U is taken, whichever is earlier.

... pleased to appoint Shri G. S. Sindhu ... he Department of Agriculture, Minis- ... Community Development and Co- ... eriod.

... *January* 1971

... —The President is pleased to appoint L ... .S. (belonging to the cadre of Rajas- ... ector of Administration in the Directo- of Exte... New Delhi, as Deputy Secretary in the stry of F... Agriculture, Community Development and eration (Department of Agriculture) with effect from the oon of the 31st December, 1970, until further orders.

The 3rd February 1971

No. 5-57/70-*AIS.*—The President is pleased to appoint Shri ...an Singh, an I.F.S. officer of the Union Terriotries Cadre, Chief Conservator of Forests, Andaman & Nicobar ...inistration, with effect from the forenoon of the 18th uary, 1971 in an officiating capacity until further orders.

S. G. SUNDARAM, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 1971

No. F. 1-18/69-*E.E.II*(.)—The President is pleased to ...nt Dr. Kerala Verma, Manager (Quality Control) in the Milk Scheme, Delhi in a substantive capacity in that .e.f. the 2nd December, 1970.

The 29th January 1971

No. A.12023/7/70-*E.E.II*(.)—The President is pleased to ...int Shri N. C. Chatterjee, an IA & AS Officer, as Finan- Adviser and Chief Accounts Officer in the Delhi Milk ...ne w.e.f. the forenoon of 23rd December, 1970 and until ...er orders.

...12025/8/70-*EE.I.*—The President is pleased to appoint ... T. Paulose, Deputy Director, in the Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, to the post of Director in the same Directorate in a temporary capacity with effect from 31st August, 1970 (F.N.) and until further orders.

The 1st February 1971

No. 9-49/68-*EE.I(Vol.II)*.—The President is pleased to appoint Shri L. Shanthi Kumar, Marine Foreman, Fisheries Training Centre, Madras, as Instructor (Marine Engineering) in the Central Institute of Fisheries Operatives (Madras Unit), with effect from the forenoon of 3rd December, 1970 and until further orders.

No. 15-39/69-*EE.I.*—In continuation to this Department's notification of even number dated the 22nd July, 1970, the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of Shri P. C. Chaddha in the post of Extension Officer (Farmers Training) for a further period of four months beyond 12th November, 1970.

No. A.12026/7/70-*EE.I.*—Shri V. S. Bendre, (C.C.S. Grade I) Under Secretary in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) has assumed the charge of the post of Registrar, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, with effect from the forenoon of the 11th January, 1971

The 2nd February 1971

No. 7-6/68-*EE.III/EE.I.*—Dr. Dinesh Kumar, Senior Research Officer (Ordinary Grade), at the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, relinquished charge of the post on the afternoon of the 30th September, 1970.

No. F. 32-31/69-*EEII*(.)—K. C. SHAHARE, Assistant Director (Planning and Coordination) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad died on the night of the 11th January, 1971.

No. F. 20-26/69-*EE.I.*—The President is pleased to appoint Shri M. Mukundan, Research Assistant, entral Institute of Fisheries Technology, Cochin, as Instructor (Operation) at the Central Institute of Fisheries Operatives, Ernakulam (Cochin) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 8th January, 1971, until further orders.

R. N. GUPTA, Under Secy.

(Department of Food)

New Delhi-1, the 20th January 1971

No. A/19011/20/70/*EI/REI.*—The President is pleased to appoint Shri G. R. Sagalgile as Assistant Director (Technical) in this Department in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 8th January 1971, until further orders.

2. Shri G. R. Sagalgile assumed charge of the post of Assistant Director (Technical) at New Delhi with headquarters at Patna with effect from 8th January, 1971.

The 21st January 1971

No. A/19011/24/70/*EI/REI.*—The President is pleased to appoint Shri Ram Bihari Doharey as Assistant Director (Technical) at the Sub-Station of Indian Grain Storage Institute at Bapatla under this Department in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 5th January, 1971, until further orders.

2. Shri Ram Bihari Doharey assumed charge of the post of Assistant Director (Technical) at Indian Grain Storage Institute, Bapatla with effect from the 5th January, 1971.

DEVAKI NANDAN GOYAL, Under Secy.

New Delhi, the 4th February 1971

*No. A*31013/1/70-*Sugar.*—The President is pleased to appoint substantively, Shri M. N. Sen Gupta and Shri A. K. Roy in the permanent Class I posts of Senior Technical Officer (Sugar Technology) and Assistant Professor of Sugar Technology Roy in the permanent Class I posts of Senior Technical Officer (Sugar Technology)/Assistant Professor of Sugar Technology/Senior Research Officer (Khandsari) at the National Sugar Institute, Kanpur, with effect from the 26th April, 1966 and the 18th June, 1966.

A. N. CHADDHA, Under Secy.

(Department of Community Development & Cooperation)

New Delhi, the 28th January 1971

No. A-24012/2/70-*Estt.(I)*.—The President is pleased to appoint Shri J. N. Chaku, an officiating Deputy Director (Co-operation) in the Department of Cooperation in the Ministry of Food, Ariculture, Community Development and Coopera-tion, as Director in a temporary officiating capacity in the same Department for the period from the forenoon of 28th January, 1971 to the afternoon of 8th February 1971.

S. V. RAMASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi-1, the 20th January 1971

No. A. 22011/270-*E.I.*—In supersession of this Ministry Notification of even number dated the 23rd December, 1970, the President is pleased to appoint the following permanent Officers of the Section Officer's Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the Service for the periods shown against each :—

S. No.	Name	From	To
1.	Shri Saran Singh	1-10-1970	31-12-1970
2.	Shri Kanwar Lal	1-10-1970	31-12-1970
3.	Dr. S.C. Seth	4-9-1970	31-12-1970
4.	Kumari P.S. Sakuntala	21-10-1970	31-12-1970
5.	Shri A.K. Verma	1-10-1970	10-11-1970
6.	Shri L.C. Wadhwa	1-10-1970	31-10-1970

2. The President is also pleased to appoint the above-noted officers as Under Secretary in the Ministry of Education and Youth Services for the aforesiad periods.

The 22nd January 1971

No. F. 15-315/64-*E.I.*—The President is pleased to permit Shri V. Ramanathan to retire from Government Service with effect from the afternoon of the 14th January, 1971.

K. S. AHLUWALIA, Under Secy.

New Delhi, the 1st February 1971

No. A.32019(1)/70-*Sur*.3.—The President is pleased to appoint Shri Bhola Nath, Zoologist, in the Headquarters of the Zoological Survey of India, to officiate as Superintending Zoologist, in the Gangetic Plains Regional Station of the Zoological Survey of India, at Patna, purely on an *ad hoc* basis, with effect from the 5th October, 1970 (Forenoon), until further orders.

S. R. AGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 1971

No. F. 8-10/69-*L*.2.—In continuation of this Ministry's Notification of even No. dated the 28th September, 1970 the President is pleased to extend the period of *ad hoc* appoint-ment of Dr. Debi Prasanna Pattanayak as Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore beyond 31st Decem-ber, 1970 for a further period till the 30th June, 1971.

N. S. BHATNAGAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th February 1971

No. F. 1-9/69-*CAI*(5).—The President is pleased to appoint Shri C. Sivaramamurti as Director, National Museum, New Delhi, with effect from the forenoon of the 1st January, 1971, and until further orders.

SARAN SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 1st February 1971

No. A.22012/1/71-*Admn*.—Consequent upon his transfer from the Monitoring Organisation, the President has been pleased to appoint Shri D. C. Kulshreshtha a temporary Engi-neer, in the Wireless Planning and Coordination Wing in the same capacity with effect from 14-1-1971 (FN) and until further orders.

The 5th February 1971

SUBJECT : Shri S. D. Nargolwala, Senior Member Finance, Posts & Telegraphs Board, New Delhi and *ex-officio* Additional Secretary to the Government of India in the Department of Communications (Posts & Telegraphs Board)—Relinquishment of charge of office.

No. A-22012/2/71-*Admn*.—Shri S. D. Nargolwala, Senior Member Finance (Posts & Telegraphs Board), New Delhi and *ex-officio* Additional Secretary to the Government of India in the Department of Communications (Posts & Telegraphs Board) relinquished charge of his office with effect from the forenoon of 5th February 1971.

O. P. SHARMA, Under Secy.

(Posts & Telegraphs Board)

New Delhi, the 29th January 1971

No. 1/35/70-*SPA*II.—The President is pleased to in public interest, the resignation of Shri S. Rana permanent officer of the Senior Administrat Indian Postal Service, with effect from the 1970, on his permanent absorption in the Miner Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.

No. 233/65/70-*STA-II*.—In continuation of t Notification of even No. dated 11-1-71, the Posts and Board is pleased to extend the local officiation in Engineering Service Class II of Shri Prithmichand, En Supervisor of the Organisation of the Regional Directo communications, Northern Region, New Delhi from 1-1- 28-2-71 or till the termination of the local arrangement, w ever is earlier.

No. 9/31/70 *SPA*-I—The P & T. Board is pleased to appo the following officers to the Postal Superintendents' S... Class II on purely local arrangement during the period showi against them *or till termination of their appointment whichever is earlier.*

	Name	Name of Circle	From	To
	S/Shri			
1.	N.C. Krishnan ..	Tamil Nadu	1-10-70	31-1-71
2.	R. Sankaranarayanan	,,	1-11-70	31-12-70
3.	A.R. Khan	West Bengal	11-6-70	22-10-70
4.	B.M. Dua	Punjab	20-5-70	31-1-71
5.	Harbans Singh ..	,,	26-12-69	31-1-71

The 4th February 1971

No. 236/4/69-*STA.II*.—The Posts and Telegraphs Board is pleased to appoint Shri S. S. Patwardhan substantively in the Telegraphs Engineering Service Class II, with effect from 11-11-68.

No. 100/129/70-*STA-I*.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Kuldip Mohan Kapoor, Scientific and Technical Officer, Grade I, Telecommunication Research Cen-tre, New Delhi from General Central Service Class-I (Junior Scale) with effect from the forenoon of the 1st January, 1971.

The 5th February 1971

No. 233/68/70-*STA-II*.—In continuation of this Board's Notification of even No. dated the 11th November, 1970, the Posts and Telegraphs Board is pleased to extend the local officiation in T.E.S. Class II of Shri Avtar Singh, Engineering Supervisor of Delhi Telephone District from 1-11-70 to 30-11-70.

No. 233/34/70-*STA-II*.—The Posts and Telegraphs Board is pleased to appoint S/Shri G. S. Jain and P. R. Balagurgi, Engineering Supervisors of Ahmedabad Telephone District to officiate in Telegraph Engineering Service Class-II, purely in local arrangement, from 7-1-71 to 31-1-71 and from 13-12-70 to 15-1-71 respectively or till the termination of the local arrangement, whichever is earlier.

No. 243/2/70-*STA-II*.—Shri A. Seshagiri Rao, Assistant Engineer Telegraphs, Microwave Project, Hyderabad, and a permanent officer of Telegraph Engineering Service Class-II retired from service with effect from 1-12-1970.

No. 233/23/70-*STA-II*.—In continuation of this Board's Notification of even number dated 17-9-70 and 23-11-70, the Posts and Telegraphs Board is pleased to extend the local officiation in Telegraph Engineering Service Class-II of S/Shri B. S. Datar and M. R. Nimkar, Engineering Supervisors of Bombay Telephones District from 14-11-70 to 28-2-71 and from 5-11-70 to 28-2-71 respectively or till the termination of the local arrangement, whichever is earlier.

The 6th February 1971

No. 214/1/70-*STA-II*.—The President is pleased to appoint Shri S. Rama Iyer, an officer of the senior scale of Telegraph Engineering Service Class I to officiate in the Junior Administrative grade of Telegraph Engineering Service Class I with from 18-1-71, on a purely temporary and *ad-hoc* basis ort-term arrangement and until further orders. He is Deputy Chief Engineer (B), P&T Directorate with same date, until further orders.

CHDEVA, Asstt. Director General (SG)

w Delhi, the 30*th January* 1971

0-*SPA.II*.—The President is pleased to grant nghal, Senior Accountant, on deputation to the Finance (Department of Economic Affairs) at for the purpose of the second proviso to F.R. 113, officiating proforma promotion to the grade ats Officers with effect from the 23rd October, 1970 ntil further orders.

SHIVANATH, Director (Staff), P&T

New Delhi, the 5th February 1971

o. 9/4/71-*SPA.II*.—The P&T Board is pleased to appoint K. Sarangapani, Senior Accountant to officiate as Accounts er, Office of the RDT, *Bombay* for the period from 0-1970 to 31-1-1971 on a purely temporary and *ad-hoc* s without prejudice to the claims of his seniors.

P. N. SAHI, Asstt. Director General, P&T

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27*th January* 1971

No. A.32014/8/70-*Admn*.—The President is pleased to appoint Shri G. R. Khatri, a permanent Grade II Officer of the C.S.S.S. cadre of the Ministry of Tourism and Civil Aviation to officiate in grade I of the service with effect from afternoon of 27-1-71 until further orders.

On his promotion, the services of Shri Khatri are placed he disposal of the Planning Commission with effect from th afternoon of 27-1-71 on temporary loan basis in exchange f Shri R. B. Bhatnagar, a grade I officer of the C.S.S.S. cadre the Planning Commission, posted in 'RS' Section of the inistry at Lucknow, against the post of senior P.A. to Commissioner for Railway Safety.

A. R. GOEL, Under Secy.

New Delhi, the 1*st February* 1971

No. A.22012/1/71-*Admn*.—On relinquishing the charge of he post of Director, in the Ministry of Shipping & Transport nsport Wing), Shri S. Ramanathan, I.A.S. assumed charge the post of Joint Secretary in the Ministry of Tourism & ivil Aviation from the forenoon of 1st February, 1971.

The 4th February 1971

No. 3-*VE*(9)/69.—The President has been pleased to approve the proforma promotion to Shri S. N. Kohli, permanent Senior Aircraft Inspector in the Civil Aviation Department and at present on deputation to the Government of Iraq, o the grade of Deputy Director/Controller of Aeronautical pection in the Civil Aviation Department with effect from e 16th April, 1970 until further orders and for so long as hri Kohli remains on deputation with the Gov nment of

T. ARUMUGHAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28*th January* 1971

No. 11-*ML*(9)/70.—The President is pleased to agree to the continued appointment of Shri I. G. Arjunani as Director (Electrical) in the headquarters office of the Director General of Lighthouses and Lightships, New Delhi on an *ad-hoc* basis upto 28th February, 1971 or till the post is filled on a regular basis in accordance with the Recruitment Rules as may be finalised in consultation with the Commission, whichever is earlier.

M. K. RAMASWAMY, Under Secy.

New Delhi-1, *the* 30*th January* 1971

No. SY-12(7)/71.—The President is pleased to appoint Shri V. Kulathu Iyer, Assistant Engineer, Public Works Department, Kerala as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 8th January, 1971 until further orders.

No. SY-12(8)/71.—The President is pleased to appoint Dr. H. Padmanabhan, Assistant Engineer, Public Works Department, Kerala, as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 8th January, 1971 until further orders.

No. SY-12(10)/71.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Vasudevan, Assistant Engineer, Public Works Department, Kerala as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 13th January, 1971 until further orders.

The 1st February 1971

No. SY-12(5)/71.—The President is pleased to appoint Shri P. A. Thampuran, Assistant Engineer, Public Works Department, Kerala as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 8th January, 1971 until further orders.

No. SY-12(9)/71.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Balakrishnan Assistant Engineer, Public Works, Department, Kerala as Assistant Executive Engineer (Mechanical) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 14th January, 1971 until further orders.

No. SY-12(6)/71.—The President is pleased to appoint Shri R. Prabhakaran Pillai, Assistant Engineer, Public Works Department, Kerala as Assistant Executive Engineer (Mechanical) in the Cochin Shipyard Project Office at Cochin in a temporary capacity with effect from the afternoon of the 8th January, 1971 until further orders.

K. BALAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 1971

No. E-1(10)/71.—On his selection for appointment as Joint Secretary in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Shri S. Ramanathan, I.A.S. relinquished charge of the post of Director (Project), Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) with effect from the forenoon of the 1st February, 1971.

No. E-1(24)/69.—On completion of her executive training in Tamil Nadu State, Smt. Bhavani Nirmal, an officer permanent in the Section Officer's grade of the C.S.S. cadre of the Ministry of Shipping and Transport, resumed charge of her duties as Section Officer in the Transport Wing of the Ministry with effect from the forenoon of the 1st February, 1971.

No. E-1(3)/71.—The President is pleased to appoint the following officers permanent in the Assistant's grade of the C.S.S. cadre of the Ministry of Shipping and Transport, to officiate in the Section Officer's grade of that Service for the periods indicated against each :—

1. Shri M. J. Thirunavakarsu—2-2-71 to 28-2-71.
2. Shri P. K. Kapur—18-1-71 to 28-2-71.
3. Shri Jagjit Singh—27-1-71 to 27-2-71.

2. Shri M. J. Thirunavakarsu (Transport Wing) is appointed to officiate as Section Officer in the Transport Wing *vice* Shri R K. Bhuchar, Section Officer, granted leave.

3. Shri P. K. Kapur (Transport Wing) is appointed to officiate as Section Officer in the Roads Wing *vice* Shri Padam Narayan, Section Officer, granted leave.

4. Shri Jagjit Singh (Transport Wing) is appointed to officiate as Section Officer in the Transport Wing *vice* Shri K. Lakshmanna, Section Officer, granted leave.

H. C. KAKAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi-1, the 30th January 1971

No. E(O)III-70PM6-189.—On transfer from Eastern Railway Shri D. N. Basak Offg. Engineer-in-Chief (Signals) Intermediate Grade is appointed to officiate as Chief Signal and Tele-Communication Engineer on the Northeast Frontier Railway with effect from the afternoon of Eighteenth December, 1970.

No. E(O)III-70PM6/155.—Shri J. Raghavan, officiating Executive Engineer, Western Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade on that Railway with effect from the afternoon of 22nd December, 1970.

No. E(O)III-70PM6-189.—Shri P. Mazumdar, Divisional Signal & Tele-Communication Engineer, Eastern Railway is appointed to Officiate as Engineer-in-Chief (Signals)/Junior Administrative Grade on that Railway with effect from the 17th December, 1970.

The 1st February 1971

No. E(O)III-70PM6/186.—Shri B. C. Srivastava, an officiating Senior Scale Officer of the Indian Railway Traffic Service, Northern Railway, is appointed to officiate in the Junior Administrative Grade of the Indian Railway Traffic Service on that Railway with effect from the afternoon of 24th December, 1970.

The 4th February 1971

No. E(O)III-70PM6-183.—Dr. H. S. Choudhury, Offg. Senior Medical Supdt. Intermediate Administrative Grade, Eastern Railway, is appointed to officiate as Chief Medical Officer on that Railway with effect from the afternoon of 24-11-70.

No. E(O)III-70PM6-44.—On transfer from Railway Board, Shri A. A. Hattangadi, Officiating Joint Director, Electrical Engineering, Junior Administrative Grade, is appointed to officiate as Superintendent Electrical in the Intermediate Administrative Grade on the Eastern Railway with effect from the afternoon of 8th December, 1970.

No. E(O)III-70PM6/180.—Shri V. N. Swamy, Officiating Engineer-in-Chief (Signals) Intermediate Administrative Grade Central Railway, is appointed to officiate as Chief Signal and Telecommunication Engineer (Construction) on that Railway with effect from the 4th December, 1970.

No. E(O)III-70PM6/111.—Shri R. N. Gheewala, Officiating Executive Engineer, Western Railway, is appointed to officiate as Deputy Chief Engineer in the Junior Administrative Grade on that Railway with effect from the afternoon of 26th December, 1970.

C. S. PARMESWARAN, Secy., Rly. Board

New Delhi, the 5th February 1971

No. ERBI/70/10/5.—Shri K. K. Roy, an Assistant in the Railway Board was promoted to officiate as Section Officer, with effect from the forenoon of 21-12-1970 till the afternoon of 16-1-1971.

No. ERBI/70/10/8.—Shri Baboo Lal, an Assistant in the Railway Board was promoted to officiate as Section Officer, with effect from the forenoon of 14-12-1970 till the afternoon of 8-1-71.

The 6th February 1971

No. ERBI/70/10/10.—Shri K. K. Handa, an Assistant in the Railway Board was promoted to officiate as Section Officer, with effect from the forenoon of 18-12-1970 till the afternoon of 15-1-1971.

C. S. PARAMESWARAN, Secy., Rly. Board & *ex-officio* Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 4th January 1971

No. 10/7/70-B&B.—In pursuance of the Notification No. 3507 dated 1-11-66 as amended *vide* Notification No. 6/4/66-B&B dated 17-1-69, of the Government of India in the Ministry of Irrigation & Power, the President is pleased to retain Shri B. R. Palta, on his superannuation as the General Manager, Beas Project, on re-employment basis, with effect from the 1st October, 1970 (Forenoon) for a period of one year.

S. L. CHATTERJI, Under

New Delhi, the January 1971

No. 13/7-71-F.1/50/68-Adm.I.—The President to appoint Shri S. Dasari to Central Power E (Class 1) Service in the grade of Assistant Dire Central Water and Power Commission (Power Win officiating capacity, with effect from the forenoon of 1 December, 1970 until further orders.

The 5th February 1971

No. 28/71-F.1/50/68.Adm.I.—The President is pleased appoint Shri R. Balaraman to Central Power Engine (Class 1) Service in the grade of Assistant Director in Central Water and Power Commission (Power Wing), in officiating capacity, with effect from the afternoon of the 12 January, 1971 until further orders.

No. 27/71-F.1/50/68-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri G. D. Kukreja to Central Power Engineering (Class I) Service in the grade of Assistant Director in the Central Water and Power Commission (Power Wing), in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 19th January, 1971 until further orders.

No. 29/71-F.1/50/68-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Ravindra P. Kapoor to Central Power Engineering (Class I) Service in the grade of Assistant Director in the Central Water and Power Commission (Power Wing), in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 21st January, 1971 until further orders.

No. 20/71-F.3/38/68-Adm.I.—The President is pleased to appoint, on promotion, Shri V. B. Rammohan to the post of Assistant Director in the Central Water and Power Commission (Power Wing), in an officiating capacity, with effect from the forenoon of the 28th November, 1970, until further orders.

The 6th February 1971

No. 21/71-F.3/3/70-Adm.I.—On relinquishing charge of the posts of Research Officer (Engineering) in the Central Water and Power Research Station, Poona, with effect from the forenoon of the 7th December, 1970, the President is pleased to promote S/Shri Y. S. Kelkar, S. T. Paliwal and P. M. Adwani to the posts of Chief Research Officer (Grade II) (Engineering) in the same Organisation, in an officiating capacity with effect from the same time and date, until further orders.

No. 22/71-F.3/3/70-Adm.I.—On reversion from the post of Chief Research Officer (Grade II) (Engineering) in the Central Water and Power Research Station, Poona, with effect from the forenoon of the 7th December, 1970. Shri M. L. Godbole assumed charge of the post of Research Officer (Engineering) in the same Organisation, with effect from the same time and date.

K. P. B. MENON, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-1, the 22nd January 1971

No. 8/4/70-CIS(I)—The President is pleased to grant Proforma officiating promotion to the following officers of the Central Information Service to the Senior Administrative

Grade (Junior Scale) of the Service with effect from the date mentioned against each, until further orders :—

S. No.	Name	Post held	Date of Promotion
1.	Shri I.P. Tewari ..	Ex-Cadre post of Director, II MC, New Delhi.	4-9-70
2.	Shri Pratap Kapur ..	Ex-Cadre post of Chief (Media), Department of Family Planning, New Delhi.	18-1-71

No. 8/4/70-*CIS(II)*—The President is pleased to appoint Shri Madan Gopal, a permanent Grade I and officiating (*ad hoc*) ...or Administrative Grade (Junior Scale) officer of the C.I.S. ... Joint Director, Publications Division, New Delhi, ...in Senior Administrative Grade (Junior Scale) of the ...n a regular basis with effect from 4-9-1970 until ...orders.

Shri Madan Gopal will continue to hold the post of Director, Publications Division, New Delhi.

Shri Madan Gopal will be on probation in Senior Ad-...rative Grade (Junior Scale) for a period of one year from ...e date of his appointment to that Grade.

The 25th January 1971

No. 5/5/69-*CIS*.—The President is pleased to appoint Shri Y. R. Mehta, a permanent Grade I and officiating Senior Administrative Grade (Junior Scale) officer of the CIS, to officiate in Junior Administrative Grade (Senior Scale) of the Service w.e.f. 18th January, 1971 until further orders.

2. Shri Mehta relinquished charge of the post of Joint Director, D.A.V.P., New Delhi on 18th January, 1971 and proceeded on leave from that date.

No. 5/5/69-*CIS(II)*.—The President is pleased to appoint Shri B. R. Bowry, a permanent Grade I and officiating Junior Administrative Grade (Senior Scale) officer of the Central Information Service, to officiate in Senior Administrative Grade (Junior Scale) of the Service w.e.f. 18th January, 1971 until further orders.

Shri Bowry relinquished charge of the post of Deputy Principal Information Officer, PIB, New Delhi on 18th January, 1971 and assumed charge of the post of Director of Public Relations in the same organisation on the same date

The 4th February 1971

No. 9/84/70-*Admn./DS(I)*.—The President is pleased to appoint Shri R. B. Sinha, a permanent Section Officer of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting, to thepost of Assistant Director (Inspection and Evaluation), Directorate of Field Publicity New Delhi, with effect from 9th December 1970 to 20th January 1971, on a purely *ad hoc* basis *vice* Shri Kartar Singh granted leave.

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

New Delhi-1, the 28th January 1971

No. PF/597/*CIS*.—The Secretary to the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby appoints Shri M. S. Krishna Rao an officiating Grade IV Officer of the Central Information Service, working as Field Publicity Officer, Dte. of Field Publicity, Guntur, to officiate in Grade III of the Central Information Service with effect from 15-1-1971, until further orders.

2. Shri M. S. Krishna Rao assumed charge of the post of Assistant News Editor, News Services Division, AIR, New Delhi, on the same date.

The 29th January 1971

No. PF/604/*CIS*.—The Secretary to the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting hereby appoints Smt. D. Janaki an officiating Grade IV Officer of the Central Information Service, working as Information Assistant, PIB, Madras to officiate in Grade III of the Central Information Service with effect from 18-1-71 (A.N.) until further orders.

2. Smt. Janaki assumed charge of the post of Assistant Editor, 'Vani', Madras on the same date.

S. PADMANABHAN, Dy. Secy., *for* Secy.

New Delhi-1, the 28th January 1971

No. 5/9/71-*B(A)*.—The President is pleased to appoint Shri K. P. Rungachary, a permanent Officer of the cadre of Station Director (Ordinary Grade), All India Radio to officiate in the cadre of Station Director (Selection Grade) with effect from the 13th January, 1971.

2. Shri K. P. Rungachary relinquished charge of the post of Director of Programmes, Directorate General, All India Radio, New Delhi, on the 13th January, 1971 and assumed charge of the post of Director, External Services Division, All India Radio, New Delhi, on the same date.

The 29th January 1971

No. 5/19/70-*B(A)*.—On his reversion to the post of Programme Executive, All India Radio, Tiruchirapalli, Shri K. P. S. Hameed, an officiating (*ad-hoc*) Assistant Station Director, All India Radio, relinquished charge of the post of Assistant Station Director, All India Radio, Tiruchirapalli, on the 6th January, 1971.

No. 25/22/64-*B(A)*.—On attaining the age of superannuation, Shri S. C. Basu, Joint Station Director, Commercial Broadcasting Service, All India Radio, Calcutta, retired from Government service on the afternoon of the 31st December, 1970

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 1st February 1971

No. 18(3)/71-*BD*—The President is pleased to appoint the following officers of the cadre of Assistant Station Engineer, All India Radio to officiate in the cadre of Station Engineer in A.I.R. on *ad hoc* basis and to post them against the posts and with effect from the dates noted against each, until furthers orders :—

S. No.	Name & Present Posting	Post	Date
1.	Shri M.S. Talwar, Asstt. Station Engineer, High Power Transmitter, Khampur, Delhi.	Station Engineer, A.I.R., Leh.	1-1-71 (F.N.)
2.	Shri K. Sunderesan, Deputy Asstt. Planning Officer (TR), DG, AIR, New Delhi.	Station Engineer, A.I.R., Udaipur.	1-1-71 (A.N.)

C.B. GIRIDHAR
Under Secretary

The 5th February 1971

No. 5/19/70-*B(A)*.—On his reversion to the post of Programme Executive, All India Radio, New Delhi, Shri P. N. Virmani, an officiating (*ad-hoc*) Assistant Station Director, Televsion Centre, All India Radio, New Delhi, relinquished charge of t he post of Assistant Station Director, Television Centre, All India Radio, New Delhi on the 22nd August, 1970 (A.N.).

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 1st February 1971

No. A-11013/8/70-*Admn.II*.—The President is pleased to appoint Shri V. D. Vyas, IAS, Deputy Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting as Director in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 1800—2000 with effect from 28th January 1971 and until further orders.

टिप्पणी 3 : यदि किसी व्यक्ति को, आवेदन पत्र भेजने के बाद, सशस्त्र सेनाओं में स्थायी आयुक्ति दे दी जायेगी, या वह सशस्त्र सेना से त्याग-पत्र दे देगा, या दुर्व्यवहार, अकुशलता के कारण या अपने स्वयं के अनुरोध पर उसे सेवाओं से निर्मुक्त कर दिया जायेगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

टिप्पणी 4 : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले इंजीनियर और डाक्टर को इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के लिये सशस्त्र सेनाओं में सेवा करनी पड़ती है तथा जिन्हें इस प्रकार की सेवा के दौरान संबद्ध नियमों के अन्तर्गत अल्पकालीन सेवा कमीशन दे दिया जाता है ।

टिप्पणी 5 : सशस्त्र सेनाओं के वालंटियर रिजर्व फौर्सेज के अधिकारियों को, जिन्हें अस्थायी सेवा के लिये बुला लिया जायें, इस परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होंगे ।

6. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन शर्तें पूरी करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी : इन नियमों के लिये "भूतपूर्व" सैनिक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी पर (चाहे लड़ाकू के रूप में अथवा अन्य प्रकार से) निरन्तर छः महीने की अवधि के लिये सेवा कर चुका है और जो दुर्व्यवहार या अकुशलता के कारण अपदस्थ, सेवोनमुक्त न होकर निर्मुक्त हुआ हो ।

स्पष्टीकरण : इन नियमों के लिये "संघ की सशस्त्र सेनाओं" में भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनायें भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें निम्नलिखित सेनाओं के सदस्य सम्मिलित नहीं, अर्थात् :

(क) असम राइफल्स,

(ख) लोक सहायक सेना, और

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स

(7) उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप रहने की इच्छा से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उगांडा तथा तंजानियां संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंजीबार) देशों से आया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिये ।

लेकिन निम्नलिखित उम्मीदवारों से पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत प्रवजन (माइग्रेट) किया हो और जो तब से आमतौर पर भारत में ही रहे हों ।

(ii) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रवजन किया हो और संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो ।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आये और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल में कोई भंग (ब्रेक) नहीं हुआ हो । लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में भंग हुआ हो और उसने 26 जनवरी 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो या शुरू कर सके तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा ।

यह शर्त भी है कि ऊपर की (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य काडर (सहायक) के ग्रेड 4 में नियुक्त के लिये पात्र नहीं होंगे ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्राविज़नल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

(2) जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या संघ-राज्य क्षेत्र, गोवा, दमन और दियु का निवासी न हो या पूर्वी अफ्रीका के केनिया, युगांडा और तन्जानिया संयुक्त गण-राज्य (भूतपूर्व तंगानिका और जंजीबार) का प्रवंजक न हो, उसे इस परीक्षा में अधिक-से-अधिक दो बार बैठने दिया जायेगा यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू हैं ।

8. (क) आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी, जो उपर्युक्त 5 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) वाली वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष न हुई हो,

शर्त यह है कि निम्नलिखित नियम 9 (ख) में उल्लिखित विधि अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उपर्युक्त तारीख को निम्नलिखित आयु न हुई हो :

(i) 24 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के

बाद प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम (9) (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो,

(ii) 23 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम 9 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(iii) 22 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रक्षिण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के दूसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(iv) 21 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(v) 20 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के चौथे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(vi) 19 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करना या कमीणन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित नियम 9 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिये किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(ख) कोई भूतपूर्व सैनिक जो उपर्युक्त नियम 5 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहता तो यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1971 को उसकी आयु 20 वर्ष हो गई हो तथा सशस्त्र सेना में कुल सेवा तीन वर्ष जोड़ कर भी 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

टिप्पणी:—किसी भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र सेनाओं मे "आव्हान पर सेवा" भी उपर्युक्त नियम 8 (ख) के लिये सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा समझी जायेगी ।

(ग) उपर्युक्त सभी मामलों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में और भी छूट दी जायेगी—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(iv) यदि उम्मीदवार अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित हो कर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर 1964 के भारत श्री लंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(vi) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(vii) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गण राज्य टंजानिया (भूतपूर्व टेंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(viii) यदि उम्मीदवार 1 जून 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो तो साथ ही 1 जून 1963 को या उसके बाद बर्मा, से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(x) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक तम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशान्ति ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(xi) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक-तम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

(घ) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित निर्धारित आयु सीमा में भी छूट दी जायेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, और सशस्त्र सेनाओं में 1963 में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) तो तीन वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और साथ ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और 1963 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों के कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) तो 8 वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का निवासी है और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो 4 वर्ष, और

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारतीय नागरिक हो और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो 3 वर्ष,

टिप्पणी-1:—नियम 8 (घ) (i) तथा 8 (घ) (ii) में विहित उपबन्ध, नियम 8 (क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v), तथा (vi), पर उल्लिखित उम्मीदवारों के लिये लागू नहीं होंगे ।

टिप्पणी-2:—नियम 8 (घ) (iii) तथा 8 (घ) (iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (iii), (iv), (v) तथा (vi), पर उल्लिखित उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे जिसने 1963 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) ।

नियम 8(घ)(iii) तथा 8(घ) (iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii) पर उल्लिखित उम्मीदवारों के लिये लागू नहीं होंगे, जिसने 1964 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) ।

उपर्युक्त परिस्थतियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी में छूट नहीं दी जायेगी ।

9 (क) उपर्युक्त नियम 5 के अनुसार आपात कालीन आयुक्त/अल्प कालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों को परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिये, या उसमें परिशिष्ट-1-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिये ।

बशर्ते कि—

(i) विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त योग्यताओं में से कोई भी योग्यता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षायें पास की हों जिसके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है ।

टिप्पणी :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार किसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाय । ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जायेगी, और यदि वे उक्त परीक्ष पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है ।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार, जो सशस्त्र सेनाओं में आपात कालीन आयुक्त/अल्प कालीन सेवा आयुक्ति के लिये उम्मीदवार की हैसियत से सेवाओं के प्रवरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, अर्थात विश्वविद्यालय । इस नियम के उप-नियम (क) में निर्धारित किसी योग्यता के लिये विश्वविद्यालय से सम्बन्ध विद्यालय, में शैक्षिक अध्ययन कर रहा हो, किन्तु सशस्त्र सेनाओं में जाने के कारण शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कोई अर्हता प्राप्त नहीं कर सका हो तो वह भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

(ग) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश चाहता है तो, उसके पास परिशिष्ट-1 में सम्मिलित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिये या परिशिष्ट -1-क में उल्लिखित कोई योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिये ।

नोट 1:—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाये । ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायेगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जायेगी, ओर यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है ।

नोट 2:— विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसमें कोई भी उपर्युक्त अर्हतायें न हों, शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उस के आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

नोट 3:—जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट-2 में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षाओं में बैठने के लिये दो बार से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यह प्रतिबन्ध 1971 में होने वाली परीक्षा से गणन किया जायेगी ।

टिप्पणी :—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषय/विषयों की परीक्षा देता है तो उसे सेवा वर्ग -1 या सेवा वर्ग 2 में सम्मिलिति सभी सेवाओं/पदों के लिये यथास्थिति (नियम 2 का संदर्भ) परीक्षा में बैठा हुआ मान लिया जायेगा जिनके लिये आयोग ने उसे प्रवेश दिया था ,

ऐसा कोई भी व्यक्ति –

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो जिसकी पत्नी पति जीवित हो, अथवा,

(ii) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित सहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस ओर से आशवस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बंधन से छूट दे सकती है ।

12. सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिये अपना आवेदन पत्र संघ लोक सेवा/आयोग के कार्यालय में भेजने के लिये अपनी यूनिट के कमांडिग आफिसर को प्रस्तुत करना चाहिये ।

जो उम्मीदवार पहले ही से सरकारी सेवा में हो, उसे परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिये ।

13. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य का दक्षता पूर्वक पालन कर सके । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नही की जायेगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किये जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी :—रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के सम्बन्ध में रक्षा सेवाओं के सैन्य विघटन मैडीकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिये पर्याप्त माना जायेगा ।

14. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकारी तब तक नही मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार इस सेवा में/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है ।

15. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

16. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

17. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

18. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किये हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिये किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रौसीक्यूशन) किया जा सकता है ।

(क) साथ ही, उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिये ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

19. परीक्षा के बाद :

(क) वर्ग 1 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम से सूची बनायेगा उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर अर्हक उम्मीदवारों की आयोग नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा,

(ख) वर्ग 2 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनायेगा, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिये निश्चित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जिन उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त देखेगा, उनकी नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा,

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को उपर्युक्त रीति से ध्यान में रखते हुए उस सेवा पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उसे सेवा/पद में, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित खाली जगहों पर उस की नियुक्ति की सिफारिश की जायेगी ।

20. यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ग 1 की सेवाओं/पदों में निर्मुक्त आपात कालीन आयुक्त/अल्प कालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों और वर्ग 2 के सेवाओं/पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अर्हकता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो न भरे गये रिक्त स्थान इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित विधि से भरे जायेंगे ।

21. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षा फल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

22. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों के समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र भरते समय वर्ग (नियम 1 का संदर्भ) में सम्मिलित विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये, जिसके सम्बन्ध में उसे परीक्षा में प्रवेश दिया गया था, बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान दिया जायेगा ।

23. नियुक्तियाँ दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेंगी । यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

24. उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी । यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा ।

25. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी०), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट 3 में संक्षेप में दी गई हैं ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखिये नियम 9)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किए गए हों ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय,
मांडले विश्वविद्यालय ।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैन्चस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेन्ट एंडस विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी आँफ आयरलैंड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय और राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल के विश्वविद्यालय :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट 1-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता-प्राप्त योग्यताएं

(देखिए नियम 9)

1 गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की 'अलंकार पदवी'

2 काशी विद्यापीठ; वाराणसी का 'शास्त्री' ।

3 फ्रांसीसी परीक्षा 'प्रापेदतीक' (Propedeutique)

4 उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद के ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

5 विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का ग्राम सेवा डिप्लोमा

6 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का वाणिज्य में डिप्लोमा ।

7 केन्द्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।

8 भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

9 श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी का 'उच्चतर पाठ्यक्रम', यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

10 शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो, अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का वरिष्ठ शास्त्री ।

11 मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में रूस के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षाएं की गई हों ।

परिशिष्ट-2

1. प्रतियोगिता परीक्षा की रूप रेखा :—

(क) निम्नलिखित पैरा 2 में उल्लिखित तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसके कुल 400 अंक होंगे ।

(ख) आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में, सशस्त्र सेनाओं में सेवा-रिकार्ड का मूल्यांकन जिसके कुल 100 अंक होंगे ।

2. परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध . . .	100	2 घण्टे
2. सामान्य अंग्रेजी . .	200	3 घण्टे
3. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है .	100	2 घण्टे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है ।

4. उम्मीदवार प्रश्न-पत्र 1 या प्रश्न पत्र 4 अथवा दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना होगा ।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्नपत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं ।

नोट 2—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के खाना 9 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. **निबन्ध** :—दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा ।

2. **सामान्य अंग्रेजी** :

(i) सार-लेखन और मसौदा-लेखन :—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे । आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजज़) दिए जाएंगे । उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा ।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य मूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(iii) शब्द-भेद (पार्टस आफ स्पीच), वाक्य-विश्लेषण, वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इनडाय रेक्ट स्पीच)।

नोट :—प्रश्न पत्र 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे ।

प्रश्न पत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है । वाक्य विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा ।

3. **सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है** :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए । जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाएंगे । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं ।

परिशिष्ट III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है ।

1. (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(i) सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष)—रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800 ।

(ii) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष)—रु० 900-50-1250 ।

(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900 ।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 210-10-270-15-300 कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 ।

नोट :—जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा, और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होनेवाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हों अपनी इस नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (बी) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(II) भारतीय विदेश सेवा (बी)

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक कांसूली एवं वाणिज्यक दूतावासों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सम्मिलित हैं । ग्रेड 4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पद	वेतन मान
ग्रेड 1	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेश में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में प्रथम और द्वितीय सचिव ।	रु० 900-50-1250 ।
एकीकृत ग्रेड 2 और 3	मुख्यालयों में सहचारी और अनुभाग अधिकारी। विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में उप कांसूल और रजिस्ट्रार ।	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 ।
ग्रेड 4	मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में सहायक।	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

टिप्पणी :—एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 400 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है ।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी) के संवर्ग के ग्रेड 4 (सहायक) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जाएगा । फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के अनुसार स्थायी किए जाएंगे, किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा। उम्मीदवारों की ग्रेड 4 में नियुक्ति सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जाएगी यदि विदेश सेवा के योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो। विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए उम्मीदवार को, एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जाएगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा ।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों । प्रशिक्षण के दौरान सन्तोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है ।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किया जाए सेवा करने को बाध्य होंगे ।

5. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सदस्य जब भारत में सेवायुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे जैसे—उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार विदेश भत्ता, निःशुल्क फर्नीचरयुक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है । ये रियायतें ऐसे सामान्य निधियों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापस ली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है ।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा-बी) (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन भी होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाए ।

7. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड 4 में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा-बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (बी०) के ग्रेड-1 के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ए०) के वरिष्ट वेतन मान में पदोन्नति के लिए रु० 900-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है ।

(iii) **रेलवे बोर्डस सचिवालय**

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती हैं, जो मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

(i) प्रवरण ग्रेड : संयुक्त निदेशक/उप सचिव, रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं।	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800

(ii)	(क) उप-निदेशकों का ग्रेड : उप-निदेशक रेलवे बोर्ड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं ।	रु० 900-50-12050 विशेष वेतन 200 रु० मासिक ।
(ख)	ग्रेड 1 : सहायक निदेशक और अवर सचिव ।	रु० 900-50-1250 ।
(iii)	अनुभाग अधिकारी ग्रेड	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 ।
(iv)	सहायक ग्रेड	रु० 210-10-280-15-300-द० रो०-15- 450-द० रो०-20-530 ।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है । जो सहायक, अनुभाग अधिकारीयों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाता है ।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों को नहीं हो सकता ।

(घ) सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ङ) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य सम्भालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे ।

(छ) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा-टिकट-आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

(iv) **सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा :**

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(1) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1) रु० 1100-50-1400 ।

(2) सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1) रु० 740-30-800-50-1150 ।

(3) अधीक्षक (श्रेणी-II राजपत्रित) रु० 350-25-500-30-590 द० रो०-30-800 ।

(4) सहायक (श्रेणी II-अराजपत्रित) रु० 200-10-270-15-300-द० रो० 15-450-द० रो० -20-530

नोट:— सहायक के ग्रेड के अधिकारी को अधीक्षक के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर अधीक्षक के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400 रु० का आरंभिक वेतन दिया जायगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायगा । इस परिवीक्षा अवधि मे उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्त पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है । तथाति, उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस संबंध में समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं उनका, ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा ।

(2) **चुनाव आयोग, भारत :**

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतन मान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रू० 210-10-270 15-300 द० रो० 15-450 द०रो० -20-530 हैं । फिर भी यह

पद केन्द्रीय सचिवालय के योजना में शामिल नहीं है तथा इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी यदि परिवीक्षाधीन सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर हर प्रकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे । इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड ये हैं :—

(1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड :— रु० 350-25-500-30-590-द०रो०-30-800-द०रो०-30-830-35-900 ।

(2) अवर सचिव ग्रेड - रु० 900-50-1250 ।

(3) पर्यटन विभाग:—

पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों का वेतन मान रु० 210-10-270-15-300-द०रो०-15-450-द०रो०-20-530 है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड चार के लिए निर्धारित है । किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं है और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते ।

सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे, और इस अवधि में उन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी । परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति दिखाने में या परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रखने का परिणाम सेवा से मुक्ति हो सकता है ।

परिवीक्षा की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, उसकी नियुक्ति पर पुष्टि कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि आगे और उस सीमा तक बढ़ायी जा सकती है जितनी कि सरकार आवश्यक समझे ।

समय समय पर इस विषय में जारी किए जाने वाले नियमों के अधीन, सहायक, सहायक निदेशक (प्रशासन) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे जिसका वेतन मान रु० 400-25-500-30-590 द० रो० -30-800 है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय
(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 1970

संकल्प

सं० 20(26)/70 सम०—देश में खनिज विकास कार्यक्रम में गति-त्वरण की दृष्टि से भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि खान तथा धातु विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाए ।

2. **नाम**

समिति, खनिज विकास समन्वय समिति कही जाएगी ।

3. **संरचना**

समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में होगी :—

सचिव, खान तथा धातु विभाग	अध्यक्ष ।
सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय व अर्थ विभाग)	सदस्य ।
सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य ।
सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय	सदस्य ।
सचिव, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	सदस्य ।
सचिव, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	सदस्य ।
सचिव, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	सदस्य ।
सचिव, योजना आयोग	सदस्य ।
संयुक्त सचिव, समन्वय का प्रभारी (खान तथा धातु विभाग)	सचिव ।

कृत्य

समिति, लौह अयस्क निर्यात प्रोत्साहन, जिसके लिए पहले ही पृथक समिति विद्यमान है, को छोड़कर खनिज विकास के समस्त पहलुओं का समन्वय करेगी और परामर्श देगी ।

समिति विभिन्न खनिजों के लिए आन्तरिक और निर्यात मांग का परीक्षण करेगी और उन क्षेत्रों का अभिज्ञान कराएगी जहां वर्धित मांग के साथ-साथ उत्पादन में समर्थ बनाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है ।

समिति, उपलब्ध खनिज संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग के लिए खनिजाधारित उद्योगों को स्थापित करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाएगी ।

समिति द्वारा, त्वरित खनिज विकास के कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में आवश्यक आधार-संरचना के विकास के लिए उपाय प्रतिपादित किए जाएंगे । इसमें मार्ग, रेल तथा पत्तन विकास, खनन-मशीनरी तथा विस्फोटों का विनिर्माण, खनिजों के परिष्करण अथवा उपयोजन पर अनुसंधान, विशेषज्ञीय वित्तीय संस्थानों के मध्यम से वित्तीय सहायता आदि सम्मिलित हैं ।

जब कभी प्रमुख गतिरोध, जिनकी प्रवृत्ति खनिज विकास के कार्यक्रम को सीमित करना होता है, विकसित होंगे, तो समिति खनिजों के निर्विघ्न और वर्धित विकास में समर्थ बनाने के लिए इस प्रकार के अवरोधनों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार करेगी । समिति, विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग और सक्रिय योगदान को लेखनीबद्ध करेगी और जब कभी आवश्यक हो सलाहकारी समितियों को भी नियुक्त करेगी ।

के० एस० रामचन्द्रन,
संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1970

सं० एस० एस० आई० (ए)-17(3)/70—औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० एस० आई० (ए)-17 (3)/70 दिनांक 25-8-1970 में, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग बोर्ड को पुनर्गठित किया गया था, बोर्ड के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा—

38. श्री पी० गंगा रेड्डी
लोक सभा सदस्य,
214, विट्ठल भाई पटेल हाउस,
नई दिल्ली ।

39. श्री सरदार आमजद अली,
लोक सभा सदस्य,
7, इलैक्ट्रिक लेन, नई दिल्ली-1

40. श्री सुल्तान सिंह,
राज्य सभा सदस्य,
21, मीना बाग, नई दिल्ली 1

ओ० आर० पद्मनाभन, अवर सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 दिसम्बर 1970

आदेश

सं० 53(1)/70 सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (4) के खंड (ख) उप-खंड (ii) के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को, कथित धारा 209 के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है—

1. श्री ए० के० घोष, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता
2. श्री आर० के० भट्टाचारजी, सहायक निरीक्षण अधिकारी, कलकत्ता ।

वी० के० वेंकटारामन, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भा० कृ० अनु० परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1970

सं० 28-1/70-समन्वय(1) भा० कृ० अनु० परि०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के अनुसार खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष को दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 से 18 नवम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए सोसाइटी की कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकीय एवं विपणन अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत किया है ।

एम० आर० कोल्हटकर, उप-सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

(पुस्तक वर्धन अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1970

सं० एफ० 7-1/70 बी० पी०—भारत सरकार संकल्प संख्या एफ० 7-7/70 बी० पी०-ii दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 के पैरा 4 के मद (ढ) के अनुसारण में निम्नलिखित व्यक्ति, पुनर्गठित बोर्ड की पहली बैठक की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपनी व्यक्तिगत हैसियत में मनोनीत किये जाते हैं :—

गैर सरकारी सदस्य

1. श्री डी० एन० मल्होत्रा
हिन्दी पाकेट बुक्स प्रा० लिमिटेड
जी० टी० रोड, शाहदरा दिल्ली-32

2. श्री जयान एच० शाह,
जैके पब्लिशिंग हाउस,
125, महात्मा गांधी रोड बम्बई-1

3. श्री एस० एन० गुहारे,
प्रबन्ध-निदेशक, श्री सरस्वती प्रेस लि०
32, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड,
कलकत्ता-9 ।

4. श्री एम० एल० जुत्शी,
मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स लि० ,
थापर हाउस, 124, जनपथ नई दिल्ली-1

5. श्री पोंकुनन वर्की,
अध्यक्ष
साहित्य प्रवर्तक कोआपरेटिव सोसायटी लि०
पोस्ट बक्स नं० 94, कोट्टायम-1

6. श्री पी० एस० जयसिंदे,
प्राकाशक,
एशिया पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०,
कालीकट स्ट्रीट, बल्लार्ड ऐस्टेट,
बम्बई-1

7. प्रो० आर० जे० तारापोरवाला,
तारापोरवाला सन्स एण्ड को० प्रा० लि०
210, डा० डी० नौरोजी रोड,
बम्बई-1

8. श्री एम० एन० राव, अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स
एसोसिएशन इन इण्डिया,
14 शकुरमा चेट्टी स्ट्रीट मद्रास-1

9. श्री आर० एन० शुक्ल,
"दि टाइम्स आफ इंडिया"
पोस्ट बाक्स नं० 213
डा० दादा भाई नौरोजी रोड
बम्बई-1

10. श्री प्राण चोपड़ा,
"दि सिटीजन एण्ड वीक ऐण्ड रिव्यू"
सी-7 निजामुद्दीन ईस्ट,
नई दिल्ली-13

11. श्री जानकी नाथ बसु,
ब्रुकलैण्ड प्राइवेट लि०
1, शंकरघोष लेन, कलकत्ता-7

12. श्री सदानन्द जी० भात्कल,
पोपुलर बुक डिपो,
बुकसेलर्स पब्लिशर्स एण्ड न्यूज एजेन्ट्स,
डा० भादकाश्रकर रोड,
बम्बई-7

13. श्रीमती शीला सुन्धु,
राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०,
8, फैंज बाजार, दिल्ली-6

14. प्रो० शान्ति नारायण, प्रिंसिपल,
हंसराज कालेज, दिल्ली-7

15. श्री डी० एन० मार्शल,
विश्वविद्यालय पुस्तकालय,
बम्बई-32

16. प्रो० ए० एम० खुशरो, इंस्टिट्यूट आफ इकोनोमिक गोथ,
यूनिवर्सिटी-ऐंकलेव,
दिल्ली-7

17. प्रो० एम० सी० शुक्ल,
सी-568, डिफेन्स कालोनी
नई दिल्ली -3

18. डा० सत्यप्रकाश,
विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

19. श्री ए० आर० देशपाण्डे,
88, वेस्ट पार्क रोड,
धननौली नागपुर

20. श्रीमती त्रिवादेवी गुप्ता,
226/4 ए० नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड
कलकत्ता-40

21. श्री यू० एस० मोहन राव,
के०-14-बीरबल रोड,
जंगपुरा, नई दिल्ली-4

22. श्री आर० एन० भट्टाचार्य,
मार्डन बुक एजेन्सी प्राइवेट लि०
10, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-12

संकल्प

विषय :– राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड का पुनर्गठन ।

सं० एफ० 7-1/70-बी०पी०II०सरकार के संकल्प सं० एफ० 23-87/65-(यू० 4)-एच० ई०–1, दिनांक 23 फरवरी के अधिक्रमण में भारत सरकार राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड का पुनर्गठन निम्नलिखित शर्तों पर करती है:–

2. बोर्ड के कार्य :

पुनर्गठित बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र सहित, देश की समस्त आवश्यकताओं को देखते हुए, पुस्तक-उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शक रेखाएं प्रस्तुत करना ;

(ख) पुस्तक-उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के उपायों पर सलाह देना ;

(ग) भारतीय लेखकों की उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें लिखने तथा भारतीय प्रकाशकों की उन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु साधनों के संबंध में सलाह देना ;

(घ) व्यवसाय में सलाह देना और मूल्यांकन करना ; लेखन, हाट, विशेषकर निर्यात संबंधी समस्याओं में अनुसंधान का आयोजन और गठन करना तथा इस बात का अध्ययन करना कि किस प्रकार भारतीय पुस्तकों का यथासंभव विस्तृत वितरण किया जा सकता है।

(ङ) पुस्तकों की कीमतें तथा उत्पादन लागत कम करने के दृष्टिकोण से उत्पादन-तकनीकों में अनुसंधान बढ़ाना ।

(च) राष्ट्रीय निष्कासन बिक्री अथवा सरकारी या गैरसरकारी प्रकाशनों आदि के वितरण की सरलता के लिए नियमित हाट संगठन की स्थापना सहित हाट सर्वेक्षण का आयोजन करना ।

(छ) विकसित देशों में पुस्तक प्रकाशन और वितरण की कुशलता और तकनीकों के नवीनतम विकास की सूचना देने के लिए निकासी गृह का कार्य करना ।

(ज) सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देना अथवा ऐसे अन्य कार्य करना जो भी सरकार द्वारा इसे सौंपे जायें ।

3. बोर्ड का मुख्यालय :

बोर्ड का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा ।

4. बोर्ड की संरचना :

(क) भारत सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष यदि अध्यक्ष किसी कारणवश किसी बैठक में भाग न ले सके, तो भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के सचिव, उस विशेष सत्र की अध्यक्षता करेंगे अथवा अध्यक्ष मनोनीत करेंगे ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(ग) औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(घ) विदेश व्यापार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(ङ) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(च) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(छ) कापीराइट रजिस्ट्रार, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ।

(ज) मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, निर्माण, आवास नगरीय विकास और परिवार नियोजन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा मनोनीत ।

(झ) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, विदेश व्यापार मंत्रालय अथवा उनके द्वारा मनोनीत ।

(ञ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(ट) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(ठ) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(ड) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक प्रतिनिधि ।

(ढ) ऐसे अन्य व्यक्ति, किन्तु जो 25 से अधिक न हों, और जिन्हें पुस्तक प्रकाशन, मुद्रण और व्यापार से संबंधित विभिन्न हितों में से भारत सरकार द्वारा, समय-समय पर मनोनीत किया जाये ।

5. सदस्यता की कार्यावधि :

बोर्ड के पदेन सदस्य के अतिरिक्त, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि सामान्यतया तीन वर्ष होंगी, जब तक कि अल्प अथवा दीर्घ अवधि निर्दिष्ट न की जाए, किन्तु, वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । जब बोर्ड का कोई सदस्य, अपने कार्यालय अथवा नियुक्ति के आधार पर सदस्य बनता है, तो उसकी बोर्ड की सदस्यता, उक्त कार्यालय अथवा नियुक्ति पर न रहने पर, समाप्त हो जाएगी । सदस्यता से सभी त्यागपत्र, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के सचिव को पेश किए जाएंगे ।

सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों पर (पदेन सदस्यों को छोड़ कर) नियुक्तियां उस प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा की जाएगी जिसने उस सदस्य को मनोनीत किया हो, जिसका स्थान रिक्त हुआ है और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति उस बकाया अवधि तक ही बोर्ड का सदस्य रहेगा, जिसके लिए कि वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके स्थान पर नियुक्ति की गई थी ।

6. बैठकें और उप-समितियां :

सामान्यतया, बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी । बोर्ड विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, समितियां नियुक्त कर सकता है, जिनकी बैठक आवश्यकता के अनुसार हो सकती है ।

[आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, सभी राज्य सरकारों और सभी संघीय प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, आयोजना आयोग को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1970

शुद्धि-पत्र

सं० एफ० 22-1/69. सी० ए० 1 (2)—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 22-1/69. सी० ए० 1(2) दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 की क्रम संख्या 2 में जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर के सामने अंकित "डा० जे० एम० सरकार" **के स्थान पर** कृपया "डा० जे० एन० सरकार" **पढ़ें** ।

सरन सिंह, अवर सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 1970

संकल्प

सं० 5-टी० एच० एल० (1)/69—होटल उद्योग के लिए आर्थिक सहायता का एक विशिष्ट साधन जुटाने के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने की एक स्कीम संकल्प सं० 5-टी० एच० एल० (35)/67 दिनांक 19-4-68 द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसे भारत राजपत्र सं० 18 दिनांक 4 मई, 1968 में कर्ज प्रदान करने के अनुदेशों के रूप में प्रकाशित किया गया और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा ।

अब यह निर्णय गिया गया है कि उक्त स्कीम को पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के अतिरिक्त, सहकारी समितियों और ट्रस्टों जिनमें धर्मार्थ ट्रस्ट भी शामिल हैं, पर भी लागू किया जाए और कर्ज प्रदान करने की कुछ शर्तों को उदार बनाया जाए ।

कर्ज के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु, उपरोक्त पैरा I में उल्लिखित संकल्प के अधीन स्थापित किए गए बोर्ड के सदस्य-सचिव अब, पर्यटन के महानिदेशक के स्थान पर, पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक होंगे ।

यथा-संशोधित स्कीम अनुबन्ध में दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और सामान्य सूचना के लिए, इसे भारत-राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० सहगल, सचिव

अनुबन्ध

होटल विकास के लिए दिए जाने वाले कर्जों से सम्बन्धित अनुदेश

(1 जुलाई 1970 तक यथा-संशोधित)

पर्यटन विभाग

होटल विकास के लिए दिए जाने वाले कर्जों से संबंधित अनुदेश

I. उद्देश्य :

देश में होटल उद्योग के लिए होटल प्रायोजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ब्याजदेय कर्जों के रूप में आर्थिक सहायता का एक विशिष्ट साधन जुटाना ।

स्पष्टीकरण :

होटल प्रायोजना से तात्पर्य यह है कि:—

(1) विदेशी पर्यटकों के रहने के उपयुक्त स्तर के होटलों अथवा होटलों का निर्माण, जिसमें

(2) पर्यटन विभाग की अनमोदित सूची में दिये गए मौजूदा होटलों अथवा मोटलों के वर्तमान स्तर में सुधार करने और/अथवा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से उनका नवीकरण और विस्तार शामिल हैं।

II. बोर्ड का गठन और उसके अधिकार :

होटल उद्योग को इन अनुदेशों के अधीन कर्ज प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। वह बोर्ड इस बात का सुनिश्चय करेगा कि आवेदक द्वारा दी गई प्रतिभूति इन अनुदेशों के अनुसार पर्याप्त है, और आवेदनों को, अपनी सिफारिशों के साथ पर्यटन नागर विमानन मन्त्रालय को भेजेगा। मन्त्रालय को कर्जों की स्वीकृत देने का अधिकार होगा परन्तु 25 लाख रुपये से अधिक के कर्जों के मामलों में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

बोर्ड, ऋणी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति से अपने लेखों की विशेष लेखापरीक्षा कराए।

बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) **अध्यक्ष :**

सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

(2) **सदस्य :**

वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) का प्रतिनिधि

(3) **सदस्य :**

निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय का प्रतिनिधि

(4) **सदस्य सचिव :**

पर्यटन का अतिरिक्त महानिदेशक

III—पात्रता :

(1) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या एक सहकारी समिति या एक ट्रस्ट, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्ट शामिल हैं, इन अनुदेशों के अधीन कर्जों के पात्र होंगे परन्तु ट्रस्ट को कर्ज देने के औचित्य का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) का परीक्षण किया जाएगा बशर्ते कि वह होटल प्रायोजना, जिसके लिए कर्ज मांगा गया है, पर्यटन विभाग द्वारा पहले से अनुमोदित हो।

(2) प्रायोजना की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए और आवेदक को बोर्ड के सामने अपने या अन्य साधनों से प्रायोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित शेष निधि जुटाने की क्षमता का प्रमाण देना होगा।

(3) होटल प्रायोजना, बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुमोदित किये जाने वाले किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इस सम्बन्ध में बोर्ड का मत अन्तिम माना जाएगा।

(4) प्रायोजना का विस्तार और स्तर उतना ही होना चाहिये जितना कि उस क्षेत्र के लिए जिसमें वह स्थित है उपयुक्त समझा जाये ताकि उसकी परिचालन लागत अलाभप्रद न सिद्ध हो।

(5) आवेदक को पर्यटन विभाग द्वारा होटलों के परिचालन के लिए समय समय पर निर्धारित विनियामक शर्तों को मंजूर करने और उनका पालन करने के लिए सहमत होना चाहिए।

IV—कर्ज की प्रमात्रा :

(1) होटल प्रायोजना की अचल परिसम्पत्तियों अर्थात भूखंड, इमारत, एवं अनबंध 'क' में उल्लिखित अन्य परिसम्पत्तियों, के मूल्य के 75% की अधिकतम सीमा तक नया निर्माण कार्य :

किसी इमारत को खरीदना और उसे होटल में बदलना भी ऋण देने के मामले में नया-निर्माण ही समझा जाएगा परन्तु शर्त यह होगी कि आवेदक आवेदन द्वारा आवृत इमारत (तों) और /अथवा अपनी अन्य परिसम्पत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करके बोर्ड को, संतुष्ट करेगा।

(2) विस्तार/नवीकरण :

किये जाने वाले खर्च का, जिसे बोर्ड द्वारा जांचा, निर्धारित एवं सहमत किया गया है, अधिकतम 50% तक।

V—शर्तें :

1. (क) इक्विटी/ऋण अनुपात :

जब आवेदक एक कम्पनी हो तो इक्विटी/ऋण का अनुपात 1:2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ईक्विटी के अन्तर्गत प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी (पेड अप ईक्विटी शेयर कैपिटल), शेयर प्रीमियम, अप्रतिदेय अधिमानी शेयर (इररिडीमेबल प्रेफेंस शेयर और जारी होने की तारीख से लेकर कम से कम 12 वर्ष की प्रतिदान अवधि (रिडेम्पशन पीरियड) की अधिमान शेयर पूंजी (प्रेफ्रेंस शेयर कैपिटल) और विकास रिबेट रिजर्व सहित मुक्त आरक्षण-निधियां (फ्री रिजर्वज) सम्मिलित होंगी। ऋण अथवा कर्जों में वे सभी उधार जिनकी वापसी उधार लेने की तारीख से लेकर पाँच वर्ष से पहले नही की जानी होती (चाहे वे कैपिटल इक्विपमेंट की खरीद के लिए मांगे गए डिबेन्चर हों अथवा कर्ज या आस्थगित भुगतान जिन मे उन पर देय ब्याज भी सम्मिलित होगा) और 12 वर्ष के भीतर प्रतिदेय अधिमान शेयर, शामिल होंगे ; लेकिन इसमें कच्चे माल, सामान और औजारों आदि के स्टाकों को दृष्टि-बंधक रख कर कार्य कर पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के प्रयोजनों के लिए बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज शामिल नहीं होंगे।

सरकारी समितियों और ट्रस्टों के मामलों में प्रायोजना के वित्त-पोषण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि ऋणी द्वारा अपनी निधियों से लगाए गए अंशदान/निवेशों और उपरोक्त परिभाषा के अनुसार लिए जाने वाले ऋण/कर्जों में कम से कम 1 : 2 का अनुपात हो।

(ख) कर्जों के लिए प्रतिभूति :

नये निर्माण अथवा नवीकरण और विस्तारकार्य के लिए दिए जाने वाले कर्जों की प्रतिभूति, इनमें से किसी भी प्रकार से हो सकती है :—

(I) होटल/मोटल सम्पत्ति की भाररहित (अनएनकम्बर्ड) अचल परिसम्पत्तियों, यथा भूखंड, इमारतों या अनुबन्ध 'क' में दी गई अन्य अचल परिसम्पत्तियों, अथवा ऐसी अन्य

भाररहित अचल सम्पत्तियों को जिन पर ऋणी का निर्बाध अधिकार हो, बंधक रखना। कर्ज के प्रचलन की अवधि के दौरान प्रतिभति का मूल्य स्वीकृत किए जाने वाले कर्ज या ऋणी द्वारा न लौटाए गए शेष कर्ज, जैसी भी स्थिति हो, की राशि के 133-1/3 प्रतिशत के बराबर होना चाहिये; अथवा

(II) एक प्रथम श्रेणी के अनुसूचित बैंक/इन्श्योरेंस कम्पनी से प्राप्त एक गारंटी बाँड देना जिसमें समस्त कर्ज की राशि और उसके ब्याज के भुगतान की गारंटी दी गई हो। जब उपरोक्त विधि के अनुसार ब्याज सहित समस्त कर्ज की राशि के भुगतान की गारन्टी देने वाले और कर्ज की अदायगी तक की समस्त अवधि को व्यापत करने वाले गारंटी बांड की प्रतिभूति पर कर्ज दिया जाएगा तो इस प्रकार दी जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य, कर्ज की राशि के 100 प्रतिशत के बराबर होगा। ऐसे मामलों में यह जरूरी नहीं, कि कर्ज की प्रमात्रा पूर्ववर्ती पैरा 4(1) में उल्लिखित होटल सम्पत्ति की अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य से सम्बन्धित हो, परन्तु शर्त यह होगी कि इस पैरे के खंड (क) में निर्धारित अनुपात वाली शर्त का पालन किया जाए।

2. प्रतिभूतियों का पुनरीक्षण :

बोर्ड, प्रत्येक कर्ज की प्रतिभूति के मूल्य का, कर्जा देने की तारीख से लेकर हर तीन वर्षों में कम से कम एक बार पुनरीक्षण करेगा। तथापि बोर्ड, दिए गए कर्ज को, प्रभावी तौर पर सुरक्षित कराने के लिए, जब भी आवश्यक समझे किसी भी समय, किसी भी प्रदत्त प्रतिभूति का पुनरीक्षण कर सकता है। यदि प्रदत्त प्रतिभूति का मूल्य अपेक्षित प्रतिभूति के मूल्य से कम पाया जाए तो ऋणों से तुरन्त अतिरिक्त प्रतिभूति जमा कराने और इस प्रकार कमी को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

3. ऋणी के निदेशक-मंडल में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति :

सरकार आवेदक के निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज) में अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को तब तक के लिए नामित करेगी जब तक कि आवेदक से कर्ज की कुछ राशि बकाया रहती है और उससे ली जानी है इस प्रकार नामित किए गए इन निदेशकों से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वे क्वालिफिकेशन शेयर रखते हों; इन निदेशकों को आवेदक हटा नहीं सकेगा और इन्हें आवेदक की वार्षिक और अन्य आम बैठकों में उपस्थित होने और भाषण देने का अधिकार होगा।

दोनों निदेशकों को वे सभी अधिकार होंगे जिनका कानून के अनुसार तथा आवेदक के अन्तर्नियमों (आर्टिक्ल्ज आफ असोसिएशन) उपनियमों के अधीन एक निदेशक द्वारा प्रयोग किया जाता है।

4. पैरा v (3) में वर्णित शर्तों का पालन करने और उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो आवेदक अपने अन्तर्नियमों/उपनियमों को संशोधित करेगा।

5. आवेदक अपने दैनिक कार्य से सम्बन्धित वे सभी सूचनाएं प्रदान करेगा जिन की मांग बोर्ड अथवा आवेदक कम्पनी के निदेशक मंडल पर सरकार द्वारा नामित निदेशकों द्वारा की जाएगी।

निदेशक मंडल में सरकार के नामित व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय, आवेदक से किसी विशिष्ट अवधि के दौरान उसके होटल/मोटल में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और /अथवा उनके नाम और उनसे लिए गये किराए आदि की जानकारी दिखाने वाले प्रतिवेदनों तथा विवरणों की मांग की जा सकती है और आवेदक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह मांगी गई विस्तृत जानकारी निदेशक मंडल पर सरकार द्वारा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों को तुरन्त उपलब्ध करायें। इसी तरह एक शर्त यह भी होगी कि आवेदक पर्यटन के महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने पर किसी भी समय अपने होटल/मोटल में विदेशी पर्यटकों के लिए स्थान की व्यवस्था करने से सम्बन्धित मांग को स्वीकार करेगा। इन शर्तों के पालन में जो त्रुटियां होगी उन पर पैरा IX में की गई व्यवस्था के अनुसार अथवा बोर्ड द्वारा निर्णीत किसी भी अन्य व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. प्रायोजना का समापन :

जिस प्रायोजना के लिए कर्ज लिया जाए उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होगा। करार में उल्लिखित नियम तारीख तक यदि प्रायोजना पूरी नहीं होगी तो उसे पैरा IX की शर्तों के अधीन एक त्रुटि समझा जाएगा। यदि अपवाद-स्वरूप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नियत तारीख के भीतर प्रायोजना को पूरा करना संभव न हो सके, तो बोर्ड वित्त मन्त्रालय से परामर्श करके और स्वयं स्पष्टीकरण के औचित्य से संतुष्ठ होने के बाद प्रायोजना के पूरा करने की तारीख को बढ़ा सकता है।

7. बीमा :

इन अनुदेशों के अधीन प्रतिभूति के रूप में आवेदक द्वारा दी गई तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों का, कर्ज की प्रमात्रा और उसके ब्याज को देखते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई राशि अथवा आवेदक द्वारा उससे अधिक निश्चित की गई किसी भी राशि के लिए चोरी, आग, बाढ़, विद्युतपात, दंगों और भूकम्पों आदि में नष्ट होने के जोखम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा कराया जाएगा, और बीमे की पालिसियां भारत के राष्ट्रपति के नाम की जायेंगी। आवेदक का यह भी कर्तव्य होगा कि वह बन्धक रखी गई परिसम्पत्तियों को बोर्ड के संतोषानुरूप अच्छी हालत में सुरक्षित रख।

VI—अदायगी का प्रकार :

(क) इन अनुदेशों के अधीन बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत कर्ज किस्तों में दिया जाएगा तथा प्रत्येक किस्त की राशि का निर्धारण बोर्ड को स्वीकार्य किसी सक्षम प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट/लोक निर्माण विभाग/चार्टर्ड अकांउटैंट आदि, द्वारा प्रमाणित किये गये, बंधक रखी गई सम्पत्ति और अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य तथा नए निर्माण कार्यों अथवा ऋण से संबद्ध काल में किए गए नवीकरणों पर आवेदक द्वारा किए गए खर्चों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ख) अगली किस्त की अदायगी प्राधिकृत होने से पूर्व आवेदक को, प्रत्येक किस्त की बाबत,, निर्धारित प्रपत्र में, अपने लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित एक 'उपयोग कर लिया गया है" इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII—ब्याज की दर और उसकी अदायगियां :

इन अनुदेशों के अधीन स्वीकृत किए गए कर्जों पर ब्याज की दर सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रमों से समय समय पर वसूल किये जाने वाली दर पर आधारित होगी। इस समय घटौती (रिबेट) सहित ब्याज की दर 7 प्रतिशत वार्षिक है। कर्ज की राशि की किस्तों और ब्याज की निर्धारित अदायगियों पर 2 प्रतिशत घटौती (रिबेट) दी जायगी। यदि आवेदक से इस सम्बन्ध में कोई चूक होती है तो उसे इस कर्ज की राशि किस्तों तथा देय बकाया ब्याज पर उस दर पर ब्याज देना होगा जिस दर पर कि कर्ज दिया गया है, और ऐसी स्थिति में 2 प्रतिशत की घटौती नहीं दी जाएगी। किन्तु सभी बकाया-राशियों (एरियरज़) का भुगतान हो जाने पर भविष्य में नियमित रूप से की गई अदायगियों पर उसे पुनः घटौती दी जा सकेगी।

कर्ज पर, अर्द्धवार्षिक रूप से ब्याज तब तक देना पड़ेगा जब तक कि कर्ज की राशि की पूरी पूरी वापसी नहीं हो जाती।

VIII—मूलधन की वापसी :

नया निर्माण :

कर्ज का भगतान 12 वर्षों की अवधि में 24 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में करना होगा; वापसी की पहली किस्त उस तारीख से तीन वर्ष बाद देय हो जायेगी जिस तारीख से कर्ज की पहली किस्त प्रदान की गई थी।

विस्तार/नवीकरण :

कर्ज की वापसी नौ वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 18 अर्द्धवार्षिक-किस्तों में करनी होगी। वापसी की पहली किस्त उस तारीख से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी जिस तारीख से कर्ज की पहली किस्त प्रदान की गई है।

किन्तु आवेदक को इस बात की छूट होगी कि वह कर्जा चुकाने की उद्दिष्ट कानूनी मुहलत के दौरान कर्ज की वापसी आरम्भ कर दे अथवा ब्याज सहित समस्त कर्ज उपर्युक्त निर्धारित कर्ज की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय लौटा दे।

XI. **त्रुटियां :** यदि आवेदक से ब्याज की अदायगी या कर्ज की वापसी की किस्तों के भुगतान या कर्ज की शर्तों के पालन में कोई चूक होती है तो बोर्ड अपने संविवेक के अनुसार और मामले के गुण-दोष का ध्यान रखते हुए नीचे बताए गए तरीकों में से किसी भी तरीके अथवा तरीकों के अनुसार उस त्रुटि पर कार्रवाई कर सकता है :—

(i) बोर्ड कर्ज की अगली किस्तें प्रदान नहीं करेगा और आवेदक कम्पनी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ब्याज सहित कर्ज की समस्त राशि, त्रुटि होने की तारीख से अगले चार महीनों के अन्दर अन्दर सरकार के पास जमा करा दे।

(ii) किस्त/ब्याज की अदायगियों में तीन बार लगातार त्रुटि होने पर बंधक रखी गई सम्पत्ति के उपभोग से आवेदक को रोक दिया जायेगा।

(iii) ऋणी का कारोबार उस से लिया जा सकता है और उस स्थिति में वह सरकार या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मनोनीत किए गए किसी भी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा चलाया जाएगा।

X. इन अनुदेशों के अनुसार कर्ज की राशि के आहरण से पूर्व आवेदक निर्धारित प्रपत्र में एक कर्ज-करार और, सर्वथा बोर्ड के संविवेक पर, एक बंधक-पत्र और/अथवा एक अनुमोदित गारंटी-कर्त्ता द्वारा एक गारंटी-बांड का निष्पादन करेगा।

XI. इन कर्जों के लेखे पर्यटन विभाग द्वारा रखे जाने चाहियें और वह कर्ज की वसूलियों और कर्ज की शर्तों के पालन पर निगरानी रखेगा।

कर्ज के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (अनुबन्ध 'ख') में आवश्यकतानुसार समर्थक प्रमाण पत्रों सहित सचिव, होटल विकास ऋण बोर्ड, पर्यटन विभाग, ट्रांसपोर्ट भवन, 1-पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुबन्ध 'क'

होटल उद्योग में अचल परिसम्पत्तियों की सूची

1. भूखंड।
2. इमारत जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी (सैनिटरी) सामान और फिटिंग्स शामिल हैं।
3. संयंत्र और मशीनरी [जिसमें भाड़ा बीमा (फ्रेट इन्श्योरेंस), आयात शुल्क, विक्रयकर, निकासी, लदान, उतराई और परिवहन प्रभार शामिल हैं] यथा :—
   (1) वातानकूलन-संयंत्र।
   (2) रेफरिजरेटर, वाटर कूलर और बर्फ बनाने का संयंत्र।
   (3) लांडरी-संयंत्र।
   (4) वाक-इन-टाइप रेफरिजरेटर और डीप फ्रीज कोल्ड स्टोरेज।
   (5) बेकरी उपकरण।
   (6) लिफ्टें (इलैक्ट्रिकल कन्वेएन्स)।
   (7) गर्म पानी की पूर्ति करने वाले उपकरण जिन में बायलर शामिल हैं।
   (8) जल मृदुकरण संयंत्र (वाटर साफ्निंग प्लांट)।
   (9) ध्वनि-व्यवस्था।
4. **विविध अचल परिसम्पत्तियों :**
   (1) ट्यूब-वेल और पम्प
   (2) रसोई घर म स्थापित उपकरण
   (3) मल निकास संयंत्र या उपकरण
   (4) स्वास्थ्य क्लब और वर्कशाप उपकरण
   (5) फिक्सड कार्पेटिंग।

अनुबन्ध 'ख'

होटल प्रायोजनाओं के लिए कर्ज का आवेदन-पत्र

भाग 'क'

1. आवेदक का नाम और पता

   (क) कम्पनी पब्लिक लिमिटेड है अथवा प्राइवेट (कंपनियों के सम्बन्ध में)

2. अधिकृत पूंजी

3. जारी पूंजी, स्वीकृत पूंजी और चुकती पूंजी

4. यदि आवेदक पहले ही कुछ होटलों का मालिक है तो उनकी संख्या; प्रत्येक होटल की बाबत इस बात का अलग अलग निर्देश किया जाए कि उसमें कितनी शैय्याओं की व्यवस्था है; उसकी मूल लागत और लेखा-पुस्तकों के अनुसार उसकी मूल्यह्रास लागत कितनी है; उसका बीमा-कृत-मूल्य और मार्किट-मूल्य क्या है। मार्किट मूल्य की पुष्टि में सम्पदा शुल्क अधिनियम/सम्पत्ति कर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन मान्य मूल्य निर्धारण प्रमाण पत्र भी देना होगा।

5. तीन वर्ष अथवा इस से अधिक समय से विद्यमान आवेदकों के मामलों में, चाहे वे कम्पनियां हों या ट्रस्ट अथवा सहकारी समितियां, पिछले तीन वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और हानि-लाभ के लेखे की प्रतिलिपियां भिजवानी होंगी (जिनमें कार्य-परिणामों, परिसम्पत्तियों और देयताओं एवं लाभांशों, यदि कोई घोषित हुए हों, का निरूपण किया गया हो) अन्य आवेदकों के मामले में जहां तक उपलब्ध हो आवश्यक सूचना भिजवाई जाए।

6. यदि आवेदक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से पहले से कोई कर्ज लिया/लिए हों या कर्ज के लिए आवेदन दिया हो तो उस (उन) कर्ज/कर्जों का ब्यौरा।

   (क) कर्ज की राशि (राशियां), कर्ज के दिए जाने की तारीख और ब्याज की दर।

   (ख) वे होटल जिनके लिए कर्ज दिया/दिए गए। यहां उन परिसम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा दें जिनकी प्रतिभूति पर कर्ज लिया/लिए गए हैं।

   (ग) कर्ज की वापसी किस तारीख से शुरू की गई अथवा की जानी है और कितनी किस्तों में की जानी है।

   (घ) क्या भूत-काल में कभी मूलधन या ब्याज किश्तों की अदायगी में चूक हुई है, और यदि हां, तो कितनी बार और किन कारणों से।

   (ङ) कर्जों की बकाया राशि, यदि कोई हो जो अभी लौटानी है।

7. निम्नलिखित का पूरा विवरण दें :—

(क) होटल, जिसके निर्माण का अब प्रस्ताव है।

(ख) होटल का स्थान: क्या कम्पनी/ट्रस्ट/ सहकारी समिति इस भू-खंड की मालिक है अथवा यह स्थान पट्टे पर लिया गया है? कृपया ब्यौरा दें।

(ग) होटल प्रायोजना की कुल लागत, जिसमें उस प्रायोजना के प्रत्येक भाग की लागत का विवरण तथा उसके साथ-साथ कुल खर्च में विदेशी मुद्रा की लागत के अंश का ब्यौरा भी दिया गया हो। साइटप्लानों और वास्तुविदी डिजाइनों की प्रतियां वास्तुविदों के नामों और वास्तुविदों के साथ किए गए करारों की प्रतियों के साथ भिजवाई जाएं।

(घ) निधि में से अब अपेक्षित कर्ज की राशि।

(ङ) क्या प्रायोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष निधियां जुटाने की व्यवस्था की जा चुकी है/यदि हां, तो कृपया दस्तावेजी प्रमाण दें।

8. यदि अपेक्षित हो तो आवेदक, होटल को बन्धक रखने के इलावा अन्य क्या प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं? और होटल की इमारत का निर्माण हो जाने तक अन्तरिम प्रतिभूति के रूप में क्या प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है?

9—क्या आवेदक को भारत सरकार के होटल विकास ऋण विषयक अनुदेशों की शर्तों की जानकारी है जिनके कि अनुसार कर्ज दिए जाते हैं, और यदि हां, तो क्या कम्पनी उन्हें पूर्णरूपेण स्वीकार करने के लिए तैयार है?

10—(क) भविष्य में प्रत्याशित कार्य-परिणाम

   (ख) क्या इन परिणामों से यह सिद्ध होता है कि आवेदक के लिए, बिना किसी कठिनाई के ऋण-परिशोधन अवधि के अन्तर्गत कर्ज की वापसी करना संभव है?

कम्पनी/ट्रस्ट/सहकारी समिति के प्रबन्ध निदेशक या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

भाग 'ख'

(पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा भरा जाएगा।)

1—क्या पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक इस संबंध में संतुष्ट हैं कि आवेदक द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे, जहां तक उनकी जांच की जा सकती है, सही हैं?

2—क्या पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक अपने तकनीकी अधिकारी से यथावश्यक परामर्श लेने के बाद इस संबंध में सामान्यता संतुष्ट हैं कि होटल प्रायोजना उस प्रायोजन के लिए उपयुक्त है जिसके लिए कि यह अभिप्रेत है?

3—क्या पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक, कम्पनी/ट्रस्ट/ सहकारी समिति द्वारा प्रार्थित कर्ज प्रदान करने की सिफारिश करते हैं? क्या वे संतुष्ट हैं कि आवेदक से ऋण-परिशोधन की अवधि के दौरान कर्ज की वापसी की युक्तियुक्त संभावनाएं हैं, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति जिस में अन्तरिम प्रतिभूति भी शामिल है, उपयुक्त और पर्याप्त है?

4—यदि आवेदक आम शर्तों में कुछ संशोधन कराना चाहता है तो पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक किस सीमा तक और किन ठोस आधारों पर उनके संशोधन की सिफारिश करते हैं ?

5—क्या पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक उक्त प्रस्ताव पर कोई विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं ?

पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा अथवा पर्यटन के महानिदेशक के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

भाग 'ग'

होटल विकास ऋण बोर्ड का निर्णय जिस पर होटल विकास ऋण बोर्ड के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली दिनांक 15 दिसम्बर 1970

संकल्प

सं० 20-पी०जी०(9)/70 पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 20-पी०जी०(13)/67 दिनांक 22 सितम्बर, 1967 के अधिक्रमण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हारबर बोर्ड को निम्नप्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है, गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि एक वर्ष की निश्चित की गई है :—

अध्यक्ष

संसद-कार्य पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री, भारत सरकार ।

उपाध्यक्ष

पोतपरिवहन तथा परिवहन के उपमंत्री, भारत सरकार ।

सदस्य

1. मत्स्यकी और पत्तन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार ।
2. राजस्व विधि और पत्तन मंत्री, गुजरात सरकार ।
3. परिवहन तथा संचार मंत्री, केरल सरकार ।
4. भवन, संचार और पर्यटन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ।
5. पत्तन मंत्री, मैसूर सरकार ।
6. वाणिज्य मंत्री, उड़ीसा सरकार
7. सहकारिता मंत्री, तमिलनाडू सरकार ।
8. पश्चिम बंगाल राज्यपाल का सलाहकार, (सिंचाई और जलमार्ग विभाग का कार्यभारी) ।
9. उपराज्यपाल, पांण्डिचेरी अथवा उनका नामित ।
10. श्री कांची कल्याणसुन्दरम् सदस्य राज्य सभा ।
11. श्री के० जे० सिकरे, सदस्य, लोक सभा ।
12. श्री हरभजन सिंह बलह्याया 1296, सैक्टर 18-सी०, चण्डीगढ़ । — व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधि ।
13. श्री सी० पी० श्रीवास्तव, भारत का पोतपरिवहन निगम, स्टीलक्रेट हाउस, डिनशोवाचा रोड़, बम्बई-20 । — पोतपरिवहन का प्रतिनिधि ।
14. श्री एल० एन० बिरला, बिरला निकेत, 3/1 राना संतोष रोड, अलीपुर, कलकत्ता-27 — अखिल भारतीय पोतवणिकों की परिषद का प्रतिनिधि ।
15. श्री डी० एम० परेख, 25, मजूभाई चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, 363, नरसीनाथ स्ट्रीट, बम्बई-9 । — पालपोत उद्योग (पश्चिम तट) का प्रतिनिधि ।
16. श्री सी० आई० आर० मकाडो, बीच रोड, तूतीकोरिन । — पालपोत उद्योग (पूर्वी तट) का प्रतिनिधि ।
17. श्री एच० एन० त्रिवेदी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ, मजदूर कार्यालय, कांग्रेस हाउस, बम्बई-4 । — श्रमिकों का प्रतिनिधि ।
18. श्री एस० सी० सी० एन्थानी पिलाई, 177, शोनोय नगर, मदरास-30 । — श्रमिकों का प्रतिनिधि ।
19. सचिव, भारत सरकार, पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय ।
20. सचिव, भारत सरकार, विदेशी व्यापार मंत्रालय, अथवा उनका नामित ।

21. सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय, अथवा उनका नामित ।

22. सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय अथवा उनका नामित ।

23. सचिव, भारत सरकार, खाद्य, कृषि समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय, (खाद्यविभाग) अथवा उनका नामित ।

24. सचिव, भारत सरकार, खाद्य कृषि, सामुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय, (कृषि विभाग) अथवा उनका नामित ।

25. सचिव, भारत सरकार, पैट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय, (पैट्रोलियम और रसायन विभाग) अथवा उनका नामित ।

26. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय अथवा उनका नामित ।

27. संयुक्त सचिव (परिवहन और संचार प्रभाग), योजना आयोग ।

28. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पूना ।

29. पोतपरिवहन का महानिदेशक, बम्बई ।

30. मुख्य आयुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा उनका नामित ।

31. अध्यक्ष, बंबई पत्तन न्यास, बम्बई ।

32. अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्त, कलकत्ता ।

33. अध्यक्ष, मदरास पत्तन न्यास, मदरास ।

34. अध्यक्ष, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् ।

35. अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन ।

36. अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम (कच्छ) ।

37. अध्यक्ष, मारमुगाओं पत्तन न्यास, मारमुगाओं (गोआ) ।

38. अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप (उड़ीसा) ।

39. मुख्यइंजीनियर और प्रशासक, तूतीकोरिन हारबर परियोजना, तूतीकोरिन ।

40. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, मंगलौर हारबर परियोजना, पानाम्बुर-मंगलौर होकर ।

41. पत्तनों का कप्तान, गोआ सरकार, डामन और ड्यू, पनाजी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd December 1970

No. 62-Pres./70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name of the officer and rank

Shri Chukkapalli Venkateswara Rao.

Inspector of Police.

District Guntur,

Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The Guntur District was hit by a severe cyclone between 17th and 19th May, 1969, resulting in dislocation of community life in the rural areas, uprooting of trees, failure of electricity and disruption of road and rail traffic. At about 1400 hours on 19th May, 1969, Shri Chukkapalli Venkateswara Rao received information that condition of the inhabitants of village Kruttula was precarious as many of the inhabitants had been washed away in the floods and the remaining were helplessly clinging to the trees and housetops. Shri Venkateswara Rao immediately proceeded to a sea-side village to procure one or two country rafts from the fishermen but could not reach the place because the Kunderu channel which had to be crossed on the way in spate. Shri Rao then obtained a private lorry and proceeded to Muttaypalem. He obtained a fisherman's country raft and with great difficulty persuaded a fisherman who brought Shri Rao and the raft to the outskirts of village Chirala. The fisherman refused to ply the raft further because of ferosily of the floods. Then Shri Rao at great personal risk plied the raft himself. After four hours of driving the raft, he reached the

village and brought six women/girls to a place of safety at the dead of nikht. Next morning, he rescued 150 more persons with the help of two fishermen and arranged for their first aid and feeding.

Shri Chukkapalli Venkateswara Rao showed conspicuous courage and initiative in saving the lives of the helpless women and men at great personal risk to his life.

2. This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th May, 1969.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL)
NEW DELHI, the 2nd January, 1971

Rules

No. 6/49/70-*CS(I)*.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1971 for selection of (1) Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962; and (2) Ex-Servicemen, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the services/posts covered by Category I and Category II respectively, as follows, are published for general information, in pursuance of the provisions contained in rule 5 of the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of vacancies) Rules, 1967, and rule 4 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and posts Class III and Class IV) Rules, 1969. The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies) Rules, 1967, and the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1969, aforesaid shall cease to be in force on and from the 29th January, 1971, and 1st July, 1971, respectively unless extended by Government.

Category I

Class II Services/posts.

(i) Central Secretariat Service—Assistants Grade.

(ii) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B).

(iii) Armed Forces Headquarters Civil Service Assistants Grade, and

(iv) Posts of Assistants in the Department of Tourism/Department of Parliamentary Affairs/Election Commission of India and certain other Departments of the Central Government not included within the purview of the Central Secretariat Service/Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Civil Service.

Category II

Class III Services/Posts

(i) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants); and

(ii) Posts of Assistants in the Directorate General, Research, Designs & Standards Organisation, Lucknow, and certain other Departments of the Central Government not included within the purview of the Railway Board Secretariat Service.

Subject to the provisions of rule 2, a candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many Services/posts as they wish to so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st December, 1971.

2. (a) Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Assistants in Class II Services/posts included in Category I.

(b) Ex-Servicemen will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Assistants in Class III Services/posts included in Category II.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part 'C' States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constituiton (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constituiton (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964 the Constituiton (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. Subject to the provisions of these Rules all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1971 will be eligible to appear at this examination.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "release" means :

(i) release as per the Scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service, from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers the year in which their normal tenure of 5 years as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short

Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.- Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to the examination.

6. Subject to the provisions of these Rules all Ex-Servicemen will be eligible to appear at this examination.

NOTE.—For the purpose of these Rules, "Ex-Servicemen" means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purpose of these Rules, "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces, namely :—

(a) Assam Rifles;
(b) Lok Sahayak Sena; and
(c) General Reserve Engineer Force.

7. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Sikkim, or
(c) a subject of Nepal, or
(d) a subject of Bhutan, or
(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizen of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

8. (A) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above, must not have attained the age of 24 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of

(i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training); and

(vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(B) An Ex-Serviceman seeking admission to the examination under rule 6 above, must have attained on 1st January, 1971, the age of 20 years and must not have attained an age exceeding 24 years by more than his total service in the Armed Forces increased by three years.

NOTE.—The period of "call up service" of an ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 8(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(D) The age limit prescribed in sub-para (A) above will also be relaxable :—

(i) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(ii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commisison training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(iii) up to a maximum of four years, if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(iv) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon.

NOTE 1.—The provisions contained in rule 8(D)(i) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A).

NOTE 2.—The provisions contained in rule 8(D)(iii) and 8(D)(ii) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in rule 8(D)(iii) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

9. (a) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above, must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

(i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

(ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

(b) A candidate who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution, *e.g.*, a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification will also be eligible to appear at the examination.

(c) An *Ex*-Serviceman seeking admission to the examination under Rule 6 above must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission, justifies his admission to the examination

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Union Public Service Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Union Public Service Commission.

10. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination to be held in 1971.

NOTE.—If a candidate actually appears in any one or more subjects he shall be deemed to have competed at the examination for all the Services/posts included in Category I or Category II as the case may be (cf. Rule 2), to which he is admitted by the Commission.

11. No person

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

12. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government service must submit their applications for this examination to their Head of Department or office concerned who will forward it to the Union Public Service Commission.

13. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled *ex*-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

14. Sucess in the examination confers no right to appointment, unless Government are satified, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

15. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

16. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

17. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

18. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period :

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

19. After the examination—

(a) the candidates competing for Services/posts included in Category I will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment; and

(b) the candidates competing for Services/posts included in Category II will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment with due regard to the number of vacancies available to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as the case may be.

20. If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/ Service Commissioned Officers in Category I Services/posts and for Ex-Servicemen in Category II Services/posts, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

21. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

22. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of this examination to the preferences expressed by a candidate at the time of his application for the various Services/posts included in the Category (cf. Rule 1) in respect of which he has been admitted to the examination.

23. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

24. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

25. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Armed Forces Headquarters Civil Service, the posts of Assistants in the Election Commission of India and the Department of Tourism, are briefly stated in Appendix III.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India

(*Vide* Rule 9)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scotish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glassgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Ireland. The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The Dacca University, The University of Sind, The Rajshahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*Vide* Rule 9)

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharti University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, *i.e.* Vishishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswa-Vidyalaya, Varanasi.
11. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX II

1. The competitive examination comprises :

   (a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 400 marks.

   (b) Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces in the case of Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the examination the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	*Time Allowed*
1 Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or both, either in Hindi or in English, Paper 2 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 9 of the application form otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstnces will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) General English :

(i) Precis writing and drafting : Questions to test the understanding and power to write English, Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangements, general expression and workmanlike use of the language.

(3) General Knowledge including Geography of India : Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) *Central Secretariat Service.*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)=Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers' Grade=Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants Grade=Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900-50-1250
Integrated Grade II and III	Attached and Section Officers at Hqrs. Vice-consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 350-25-500-30 590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad.	Rs. 210-10-270-15 300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE.—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment Cadre seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S.(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE.—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900—50—1000—60—1600—50—1800.

(iii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :

(i) Selection Grade : such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs. 1110-50-1300 60-1600-100-1800.
(ii) (a) Dy. Directors Grade : Such posts of Dy. Directors, Railway Boards as may from time to time be held by Officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs. 900-50-1250 plus specialpay of Rs. 200/-p.m.
(b) Grade I : Assistant Directors & Under Secretaries.	Rs. 900-50-1250
(iii) Section Officer Grade	Rs. 350-25-500 30-590-EB-30 800-EB-30-830 35-900.
(iv) Assistants Grade	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants plomoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(d) Officer recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service.*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

(1) Senior Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 1,100—50—1,400.

(2) Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 740—30—800—50—1,150.

(3) Superintendent (Class II—Gazetted)—Rs. 350 25—500—30—590—EB—30—800.

(4) Assistant (Class II—Non-gazetted)—Rs. 210—10 270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Superintendent shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Superintendent.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grades of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

(2) *Election Commission, India.*

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) *Section Officers' Grade*—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(2) *Under Secretaries' Grade*—Rs. 900—50—1,250.

(3) *Department of Tourism.*

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 as prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the probationer in his appointment, or if his work or conduct, has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 14th December 1970

RESOLUTION

Mineral Development (other than Iron Ore) Coordination Committee

No. 20(26)/70-Cordn.—With a view to speed up the programme of mineral development in the country, the Government of India have decided to appoint a Committee under the Chairmanship of Secretary, Department of Mines & Metals.

2. *Title*

The Committee will be called the Mineral Development Coordination Committee.

3. *Constitution*

The Constitution of the Committee will be as under :

Chairman

Secretary, Department of Mines & Metals.

Members

Secretary, Ministry of Finance (Expenditure & Economic Affairs).

Secretary, Department of Industrial Development.

Secretary, Ministry of Foreign Trade.

Secretary, Ministry of Transport & Shipping.

Secretary, Ministry of Steel & Heavy Engineering.

Chairman, Ministry of Railways (Railway Board).

Secretary, Planning Commission.

Secretary

Joint Secretary, in charge of Coordination (Department of Mines & Metals).

4. *Functions*

The Committee will coordinate and advise on all aspects of mineral development, except Iron ore export promotion for which a separate committee already exists.

The Committee will examine the internal and export demand for various minerals and identify the areas where special efforts are necessary to enable production to keep pace with increasing demand.

The Committee will also initiate necessary steps for setting up mineral based industries to make full use of the available mineral resources.

Measures for developing the necessary infra-structure in the country to meet the needs of a programme of rapid mineral development will be formulated by the Committee. This would include road, railway and ports development, manufacture of mining machinery and explosives, research on beneficiation or utilization of minerals, financial support through specialised financial institutions, etc.

As and when major impediments develop which have a tendency of limiting the progress of mineral development, this Committee will consider the steps necessary to remove such obstacles to enable uninterrupted and accelerated development of minerals. The Committee may enlist cooperation and active participation of various State Governments, and may also appoint Advisory Committees as and when found necessary.

K. S. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 18th December 1970

No. SSI(A)-17(3)/70.—In the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Resolution No. SSI(A)-17(3)/70, dated 25-8-1970, under which the Small Scale Industries Board was reconstituted, the following may be included in the list of members of the Board :—

38. Shri P. Ganga Reddy, Member, Lok Sabha, 214, Vithal Bhai Patel House, New Delhi.

39. Shri Sardar Amjad Ali, Member, Lok Sabha, 7, Electric Lane, New Delhi-1.

40. Shri Sultan Singh, Member, Rajya Sabha, 21, Meena Bag, New Delhi.

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

ORDER

New Delhi, the 17th December 1970

No. 53(1)/70-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1) of 1956), the Company Law Board hereby authorises the following officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209 :

1. Shri A. K. Ghosh, Joint Director, Inspection, Calcutta.

2. Shri R. K. Bhattacharjee, Assistant Inspecting Officer, Calcutta.

V. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture—ICAR)

New Delhi, the 19th December 1970

No. 28(1)/70-CDN(I).—Under the Provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate, Chairman, Agricultural Prices Commission, as a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research of the Society with effect from 19th December, 1970 to 18th November, 1972.

M. R. KALHATKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi-1, the 15th December 1970

RESOLUTION

SUBJECT :—*National Book Development Board—Reconstitution of—.*

No. F. 7-1/70-BP.II.—In supersession of the Government Resolution No. F. 23-87/65(U.4)-HE.1, dated the 23rd February, 1967 the Government of India are pleased to reconstitute the National Book Development Board with the following provisions :—

2. *Functions of the Board*

The functions of the reconstituted Board shall be as follows :—

(a) To lay down guidelines for the development of the book industry in the context of the overall requirements of the country, including those in the field of higher education;

(b) To advise on measures for the promotion of the book industry and trade;

(c) To advise on measures for encouraging Indian authors to write suitable textbooks and Indian publishers to publish them;

(d) To assess and advise in undertaking, organising and carrying out research into writings, marketing problems particularly in export areas, and to study how best the widest possible distribution of Indian books could be obtained;

(e) To undertake and promote research in the production techniques with a view to bringing down the cost of production and prices of books;

(f) To undertake marketing surveys to streamline the distribution system, including national clearance sales or setting up of a regular marketing organisation for the distribution of official and non-official publications etc.;

(g) To act as a clearing house of information on the latest developments in the skills and techniques of book publishing and distributing in advanced countries;

(h) To advise Government on such matters or to perform such other functions as are referred to it by the Government.

3. *Headquarters of the Board*

The headquarters of the Board shall be at New Delhi.

4. *Composition of the Board*

(a) Chairman to be nominated by the Government of India. If for any reason the Chairman is unable to attend any meeting, the Secretary to the Government of India in the Ministry concerned would preside or nominate a Chairman for that particular session.

(b) One representative of the Ministry of Education.

(c) One representative of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade.

(d) One representative of the Ministry of Foreign Trade.

(e) One representative of the Ministry of Information and Broadcasting.

(f) One representative of the Ministry of Finance.

(g) Registrar of Copyrights, Ministry of Education and Youth Services.

(h) Chief Controller, Printing and Stationery, Ministry of Works, Housing, Urban Development and Family Planning or his nominee.

(i) Chief Controller, Imports and Exports, Ministry of Foreign Trade or his nominee.

(j) One representative of the University Grants Commission.

(k) One representative of the Council of Scientific and Industrial Research.

(l) One representative of the National Council of Educational Research and Training.

(m) One representative of National Book Trust.

(n) Such other persons, not exceeding twenty five as may be nominated by the Government of India from time to time, from among the various interests connected with book publishing, printing and trade.

5. *Tenure of Membership*

The tenure of the Chairman and each member of the Board other than an *ex-officio* member, shall normally be three years, unless a shorter or a longer term is indicated but he will be eligible for reappointment. Where a member of the Board becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Board shall terminate when he ceases to hold that office or appointment. All resignations of membership shall be submitted to the Secretary to the Government of India in the Ministry concerned.

All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person appointed to a casual vacancy shall be a member of the Board for the residue of the term for which the person whose place was filled would have been a member.

6. *Meetings and Sub-Committees*

The Board shall ordinarily meet at least once a year. The Board may set up Committees for specific purposes which may meet as frequently as required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, all Ministries of the Government of India and their Departments, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

(Book Promotion Section II)

No. F. 7-1/70-BP.II.—In pursuance of item (n) of para 4 of the Government of India Resolution No. F. 7-1/70-BP.-II, dated the 15th December, 1970 the following persons are nominated, in their individual capacity, as members of the reconstituted National Book Development Board for a period of three years from the date of the first meeting of the reconstituted Board :—

Non-official Members

1. Shri D. N. Malhotra, IInd Pocket Books Private Limited, G. T. Road, Shahdara, Delhi-32.
2. Shri Jaman H. Shah, Jaico Publishing House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.
3. Shri S. N. Guha Ray, Managing Director, Sree Saraswaty Press Limited, 32, Acharya Praphulla Chandra Road, Calcutta-9.
4. Shri M. L. Zutshi, M/s. Ballarpur Paper and Straw Board Mills Ltd., Thapar House, 124, Janpath, New Delhi-1.
5. Shri Ponkunnam Varkey, President, Sahitya Pravarthaka Cooperative Society Ltd., Post Box No. 94, Kottayam-1.
6. Shri P. S Javasinghe, Publisher, Asia Publishing House Private Ltd., Calicut St., Ballard Estate, Bombay-1.
7. Prof. R J. Taraporevalla, Taraporevala Sons and Co. Pvt. Ltd., 210, Dr. D. Naroji Road, Bombay-1.
8. Shri M. N. Rao, President, The Federation of Publishers and Booksellers Associations in India, 14, Sunkurama Chetty St., Madras-1.
9. Shri R. N. Shukla, "The Times of India", Post Office Box No. 213, Dr. Dadabhoy Naoroji Road, Bombay-1.
10. Shri Pran Chopra, "The Citizen and Weekend Review", C-7, Nizamuddin East, New Delhi-13.
11. Shri Janakinath Basu, Bookland Private Ltd., 1, Sankar Ghosh Lane, Calcutta-7.
12. Shri Sadanand G. Bhatkal, Popular Book Depot, Booksellers Publishers and News Agents, Dr. Bhadkamkar Road, Bombay-7.
13. Smt. Shiela Sandhu, Rajkamal Prakashan Private Ltd., 8, Faiz Bazar, Delhi-6.
14. Prof. Shanti Narain, Principal, Hans Raj College, Delhi-7.
15. Shri D. N. Marshall, University Library, Bombay-32.
16. Prof. A. M. Khusro, Institute of Economic Growth, University Enclave, Delhi 7.
17. Prof. M. C. Shukla, C-568, Defence Colony, New Delhi-3.
18. Dr. Satya Prakash, Head of the Department of Chemistry, University of Allahabad, Allahabad.
19. Shri A. R. Deshpande, 88, West Park Road, Dhantoli, Nagpur.
20. Smt. Chitrita Devi Gupta, 226/4-A, Netaji Subhash Chandra Bose Road, Calcutta-40.
21. Shri U. S. Mohan Rao, K-14, Birbal Road, Jangpura, New Delhi-14.
22. Shri R. N. Bhattacharya, Modern Book Agency Private Limited, 10, Bankim Chatterji Street, Calcutta-12.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

New Delhi, the 18th December 1970

CORRIGENDUM

No. F. 22-1/69-*CAI*-2.—Please *read* Dr. J. N. Sarkar *in place of* Dr. J. M. Sarkar occurring against Jadavpur University, Jadavpur at S. No. 2 of this Ministry's Notification No. F. 22-1/69-CAI-2, dated the 17th October, 1970.

SARAN SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 13th July 1970

RESOLUTION

No. 5-THL(1)/69.—In order to provide the Hotel Industry with a specialised source of financial assistance, a scheme for the grant of loans was sanctioned in Resolution bearing No. 5-THI(35)/67, dated 19th April, 1968 and published in the Gazette of India No. 18 dated 4th May, 1968 in the form of Instructions for the grant of loans and was amended from time to time.

It has now been decided to extend the scheme to Co-operative Societies and Trusts including Charitable Trusts, in addition to Public or Private Limited Companies and to liberalise certain terms and conditions for the grant of loans.

In place of Director General of Tourism the Additional Director General of Tourism will be the Member-Secretary of the Board set up under the Resolution mentioned in para one above, to consider applications for the grant of loans.

The scheme as amended is given in the Annexure.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. SAHGAL, Secy.

ANNEXURE

INSTRUCTIONS FOR THE GRANT OF LOANS FOR HOTEL DEVELOPMENT

(As amended up to 1st July 1970)

I. *Objective*

To provide the Hotel Industry in the country a specialised source of financial assistance in the shape of interest bearing loans for the implementation of hotel projects.

Explanation :

Hotel project means :

(1) the construction of hotels or motels of the standard suitable for occupancy by foreign tourists and includes

(2) renovation and expansion of existing hotels or motels on the approved list of the Department of Tourism with a view to improving their existing standard and/or to providing additional facilities.

II. *Constitution and Powers of the Board*

A Board will be set up to consider applications for the grant of loans to the Hotel Industry under these instructions. It shall satisfy itself that the security offered by the applicant is sufficient in accordance with these instructions and shall make its recommendations on the applications to the Ministry of Tourism & Civil Aviation. The Ministry shall have powers to sanction the loans provided that loans exceeding Rs. 25 lakhs shall require the approval of the Government of India in the Ministry of Finance.

The Board may also require the Borrower to undergo a special audit of their accounts by the Comptroller & Auditor General of India or his nominee.

The Board shall consist of the following :

(1) *Chairman*

Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

(2) *Member*

Representative of the Ministry of Finance (Department of Expenditure).

(3) *Member*

Representative of the Ministry of Works, Housing & Supply.

(4) *Member-Secretary*

Additional Director General of Tourism.

II. *Eligibility*

(1) A Public limited company or a private limited company or a cooperative society or a Trust including charitable trust is eligible for loans under these instructions subject to each Trust Deed being examined to determine the advisability of giving a loan to the Trust provided the hotel project for which the loan is sought has the prior approval of the Department of Tourism.

(2) The project should be financially sound and the applicant should adduce evidence before the Board as regards its capacity to raise the balance of funds required for completing the project from its own or other resources.

(3) The hotel project should be located in an area of tourist importance as may be approved by the Board from time to time. The opinion of the Board in this respect will be final.

(4) The project should be of a size and standard considered suitable for the area in which it is located so that the cost of its operation is not uneconomical.

(5) The applicant should be agreeable to accept and abide by the regulatory conditions for the operation of hotels prescribed by the Department of Tourism from time to time.

IV. *Quantum of Loan*

(1) New construction up to a maximum of 75% of the value of the fixed assets of the hotel project namely land, building and other assets as specified in Annexure 'A'.

Purchase and conversion of a building into hotel will be treated as new construction for granting loans, provided the applicant satisfies the Board by offering the building(s) covered by the application and/or the applicant's other assets as securities.

(2) *Expansion/Renovations* : Up to a maximum of 50% of the cost to be incurred, as examined, assessed and agreed to by the Board.

V. *Terms and Conditions*

1. (a) *Equity/Debt Ratio* :

Where the applicant is a Company the equity/debt ratio should not exceed 1 : 2. The equity will comprise paid-up equity share capital, share premium, irredeemable preference shares, preference share capital of redemption period of not less than 12 years from the date of issue, and free reserves including development rebate reserve. Debt or loan will include all borrowings repayable not earlier than five years from the date of borrowing (whether debentures, loan or deferred payment including interest thereon, for the purchase of capital equipment) and preference shares redeemable not later than 12 years; but does not include loans from banks for working capital purposes against hypothecation of stocks of raw materials, stores, tools etc.

In the case of cooperative societies and trusts the financing pattern of the project should be such that the ratio of the borrower's contribution/investment from his own funds, to the debt/loans as defined above should be at least 1 : 2.

(b) *Security for loans* :

Loans for new construction or for renovation and expansion will be secured either by

(i) mortgage of unencumbered fixed assets of the hotel/moter property namely land buildings and other fixed assets as described in Annexure 'A' or other unencumbered immovable property over which the Borrower has clear title. The value of security shall be equal to 133 and 1/3% of the amount of loan proposed to be sanctioned or of the amount of loan remaining unrepaid by the Borrower as the case may be, throughout the period of currency of the loan or,

(ii) by a guarantee bond from a first class scheduled bank/insurance company guaranteeing repayment of the entire loan amount and its interest. When the loan is secured by a guarantee bond as aforesaid guaranteeing the repayment of the full amount of loan with interest and covering entire period of repayment of loan, the security so offered shall be of the value equal to 100% of the amount of loan. The quantum of loan in this case need not be related to the value of the fixed assets of the hotel property, referred to in para IV(i) *Supra* provided the ratio prescribed in clause (a) of this para above is satisfied.

2. *Review of securities* :

The Board shall conduct a review of the value of the security in respect of each loan at least once in every three years from the date of the grant of loan. The Board may, however, conduct such a review at any time it likes in respect of any security furnished, where it considers it necessary to do so to effectively safeguard the loan advanced. If this value is found to be less than the security required, the Borrower shall be asked to make up the shortfall immediately by furnishing additional security.

3. *Government nominee on the Board of Directors of the Borrower* :

The Government will nominate Directors not exceeding two on the applicant's Board of Directors for so long as any sums remain due and outstanding in respect of the loan from the applicant to the Government. The Directors so nominated shall not be required to hold any qualification shares, shall not be removable by the applicant and shall have the right to attend and address the applicant's annual and other general meetings.

Both the Directors shall exercise all the rights of a Director exercisable under the Law and under the Articles of Association/By-laws of the applicant.

4. The applicant shall, if necessary, amend their Articles of Association/By-laws to provide for the requirements mentioned above, to give effect to the conditions mentioned in Para V(3).

5. The applicant shall furnish in all information regarding their day-to-day working which may be called for either by the Board or by the Directors nominated by the Government on its Board of Directors.

The Government's nominee(s) on the Board may at any time call upon the applicant to submit returns or statements of the number and/or names of foreign tourists lodged in its hotel/Motel during any specified period and the rent etc. charged from them and the applicant shall forthwith furnish detailed information asked for to the Government nominee(s) on the Board. It shall also likewise be a condition of the application that the applicant shall honour the requisition of the Director General of Tourism or any person authorised by him for accommodating foreign tourists in the applicant's hotel-Motel at any time after giving notice. Defaults in complying with these conditions will be dealt with as provided for in Para IX or otherwise as may be decided by the Board.

6. *Completion of the project* :

The project for which the loan is to be taken will have to be completed within the period stipulated by the Board.

Non-completion of the project by the target date specified in the agreement, shall be treated as a default in terms of Para IX. If, in exceptional circumstances, the completion of the project is not possible within the specified date, the Board may, in consultation with the Ministry of Finance, and after satisfying itself as to the validity of the justification, decide to extend the date of completion of the project.

7. *Insurance* :

The property and assets offered by the applicant and accepted by the Board as Security under these instructions shall be insured to cover risks arising from theft, fire, flood, lightining, riots and Earthquakes for an amount determined by the Board having regard to the quantum of loan and interest thereon, or for any higher amount that the applicant may decide, and the insurance policies assigned to the President of India. It shall also be the duty of the applicant to maintain the aforesaid mortgage assets in the best condition to the satisfaction of the Board.

VI. *Mode of Payment*

(a) The loan sanctioned under these instructions shall be paid to the applicant by the Board in instalments, each instalment to be determined having regard to the value as certified by the competent authority acceptable to the Board e.g. District Magistrate/ P.W.D./Chartered Accountants etc. of the mortgage property and other assets as well as the value of the new constructions or the expenditure incurred by the applicant in respect of the renovations etc. at the relevant point of time.

(b) The applicant shall be required to submit a utilisation certificate in the prescribed form duly verified by their auditors in respect of each instalment before the next instalment is authorised for payment.

VII. *Rate of Interest and its Payments*

The rate of interest on the loans sanctioned under these instructions will be based on the rate charged by the Government from industrial undertakings from time to time. At present this rate of interest including the rebate works out to 9¼% per annum. A rebate of 2¼% will be allowed on punctual payments of instalments of the loan amount and interest. In case the applicant makes any default it shall be liable to pay interest at the rate at which the loan has been advanced both in respect of instalments of amount of the loan and of the interest due and outstanding and no rebate of 2¼% will be allowed. When all the arrears are paid, rebate on future punctual payments will be restored.

Interest on the loan will be payable on a half yearly basis until the loan is repaid in full.

VIII. *Repayment of Principal*

New Construction : The loan will be repayable in twenty four half-yearly instalments over a period of twelve years, the first instalment being due after three years from the date on which the first instalment of the loan is made available.

Expansion/Renovation : The loan will be repayable in eighteen half-yearly instalments over a period of nine years, the first instalment to be paid after one year from the date on which the first instalment of the loan is made available.

It will, however, be open to the applicant to commence repayment of the loan during the period of moratorium mentioned, or to repay the entire loan with interest at any time before the end of the periods of loan prescribed above.

IX. *Defaults*

If any default is committed by the applicant either in the payment of the interest or repayment of the loan instalments or in complying with any of the terms and conditions of the loan then the Board may, at its discretion and depending on the merits of the case deal with the default in any one or more of the following ways :—

(i) The Board shall not pay further instalments of the loan and shall require the applicant company to deposit the entire amount of loan with interest with the Government, within 4 months of the date of default.

(ii) In the event of 3 successive defaults in the payment of instalments/interest taking place, the mortgage will be foreclosed.

(iii) the business of the borrower may be taken over and its business run by the Govtrnment or by any nominee or any agency of the Government specifically designated for this purpose.

X. The applicant shall before the drawal of the loan in terms of these instructions execute a loan agreement and a mortgage deed and/or Guarantee Bond from an approved Guarantor at the sole discretion of the Board in the prescribed form.

XI. Accounts of these loans should be maintained by the Department of Tourism which shall also watch their recoveries and the fulfilment of the terms and conditions of the loan.

Applications for loans shall be submitted in the prescribed proforma (Annexure 'B') with supporting certificate wherever necessary to Secretary, Hotel Development Loans Board, Department of Tourism, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-1.

ANNEXURE 'A'

LIST OF FIXED ASSETS IN THE HOTEL INDUSTRY

1. Land.

2. Building, including sanitary wares and fittings.

3. Plant and Machinery (including freight insurance, import duty sales tax, clearing loading, unloading and transport charges) *viz.* :

(i) Air-conditioning plant.
(ii) Refrigerators, water cooler and ice making plant.
(iii) Laundry plant.
(iv) Walk-in-type refrigerator and deep freeze cold storage.
(v) Bakery equipment.
(vi) Lifts (electrical conveyance).
(vii) Hot water supply equipment including boilers.
(viii) Water softening plant.
(ix) Sound system.

4. Misc. fixed assets.

(i) Tube well and pump.
(ii) Installed kitchen equipment.
(iii) Sewage disposal plant or apparatus.
(iv) Health, club and workshop equipment.
(v) Fixed carpeting.

ANNEXURE 'B'

APPLICATION FOR GRANT OF LOAN FOR HOTEL PROJECTS

PART A :

1. Name and address of the applicant

(a) Whether public limited or private company, (in case of companies).

2. Authorised capital.

3. Issued, subscribed and paid-up capital.

4. Number of hotels, if any already owned by the applicant, indicating separately in respect of each hotel its bed capacity, its original cost and depreciated cost as per the books, its insured value and market value. The market value should be supported by a certificate of valuation recognised under the provisions of Estate Duty Act/Wealth Tax Act.

5. In the case of applicants whether companies or Trusts or Cooperative societies in existence for three years or more, copies of audited balance sheets and profit and loss accounts for the last three years (indicating working results, assets and liabilities and divided, if any declared) may be furnished. In the case of others, necessary information to the extent available may be furnished.

6. Particulars of loan(s) if any already granted to or applied for by the applicant to banks and other financial institutions.

(a) Amount(s) of loan, date of grant and rate of interest.

(b) Hotels against which the loan(s) was/were granted. Give full particulars of the assets against which the loan(s) is secured.

(c) Repayment(s) commenced or to commence from which date and to be made in how many instalments.

(d) Whether there has been in the past any default in the payment of instalments of either principal or interest, if so, on how many occasions, and for what reasons.

(e) Outstanding Balance of loans, if any.

7. Full particulars of :—

(a) Hotel now proposed to be built.

(b) Location : Does the Company/Trust/Cooperative Society own the land or was it obtained on lease ? Please give particulars.

(c) Total cost of the hotel project indicating the cost of each of its components, including that of the foreign exchange element in the over all expenditure. Copies of the site plan and architectural designs should be furnished together with the names of the architects and copies of agreements entered into with architects.

(d) Amount of loan now required from the fund.

(e) Have arrangements been made to provide the balance of funds needed for the completion of the project. If so, please provide documentary evidence.

8. What security, in addition to the mortgage of the hotel is the applicant prepared to offer, if so, required and pending the building of the hotel what interim security is proposed to be furnished ?

9. Whether the applicant is aware of the terms of the Government of India "Hotel Development Loan Instructions" on which loans are granted for hotel development and if so, whether the company is prepared to accept them in their entirety.

10. (a) Anticipated working results in future and

(b) Whether such results fully establish the possibility of the applicant repaying the loan within the period of amortisation without any difficulty ?

To be signed by the Managing Director or other authorised official of the Company/Trust/Cooperative Society.

PART B :

(To be filled by the Additional Director General of Tourism)

1. Is the Additional Director General of Tourism satisfied that the particulars furnished above by the applicant are correct to the extent that they can be verified ?

2. Is the Additional Director General of Tourism generally satisfied after making such consultation as he deems necessary from his Technical Officer, that the hotel project is suitable for the purpose for which it is intended ?

3. Does the Additional Director General of Tourism recommend the grant of loan applied for by the Company/Trust/Cooperative Society ? Is he satisfied that there is a reasonable prospect of the applicant being able to repay the loan within the period of amortisation and the security offered by the applicant including the interim security is good and sufficient ?

4. In case the aplicant desires any modification of the usual terms to what extent does the Additional Director General of Tourism recommend them and on what precise grounds ?

5. Has the Additional Director General of Tourism any special comments to offer on the proposal ?

To be signed by the Additional Director General of Tourism or other authorised officer of the Director General of Tourism.

PART C

Decision of the Hotel Development Loans Board to be signed by the Secretary, Hotel Development Loans Board.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th December 1970

No. 20-PG(9)/70.—In supersession of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 20-PG(13)/67, dated the 22nd September, 1967, the Government of India have decided that the National Harbour Board shall be reconstituted as follows, the term of the non-official members being fixed as one year :—

Chairman

Minister for Parliamentary Affairs, Shipping and Transport, Government of India.

Vice-Chairman

Deputy Minister for Shipping and Transport, Government of India.

Members

1. Minister for Fisheries and Ports, Government of Andhra Pradesh.
2. Minister for Revenue, Law and Ports, Government of Gujarat.
3. Minister for Transport and Communications, Government of Kerala.
4. Minister for Buildings, Communications and Tourism, Government of Maharashtra.
5. Minister for Ports, Government of Mysore.
6. Minister for Commerce, Government of Orissa.
7. Minister for Cooperation, Government of Tamil Nadu.
8. Adviser to the Governor of West Bengal (Incharge of Irrigation and Waterways Department).
9. Lieutenant Governor, Pondicherry, or his nominee.
10. Shri Kanchi Kalyanasundaram, Member, Rajya Sabha.
11. Shri J. J. Shinkre, Member, Lok Sabha.
12. Shri Harbhajan Singh Balhaya, 1296, Sector 18-C, Chandigarh—Representative of Trade and Industry.
13. Shri C. P. Srivastava, Shipping Corporation of India Ltd. Steelcrete House, Dinshaw Wacha Road, Bombay-20—Representative of Shipping.
14. Shri L. N. Birla, Birla Niket, 3/1, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta-27—Representative of the All India Shippers Council.
15. Shri D. M. Parekh, 25, Bhagubhai Chambers, 3rd Floor, 363, Narsinatha Street, Bombay-9—Representative of Sailing Vessels Industry (West Coast).
16. Shri C. I. R. Machado, Beach Road, Tuticorin—Representative of Sailing Vessels Industry (East Coast).
17. Shri H. N. Trivedi, President, Indian National Port and Dock Workers' Federation, Mazdoor Karyalaya, Congress House, Bombay-4—Representative of labour.
18. Shri S. C. C. Anthoni Pillai, 177, Shenoynagar, Madras-30—Representative of labour.
19. Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping & Transport
20. Secretary to the Government of India Ministry of Foreign Trade, or his nominee.
21. Secretary to the Government of India, Ministry of Industrial Development and Internal Trade, or his nominee.
22. Secretary to the Government of India, Ministry of Defence, or his nominee.

23. Secretary to the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Department of Food), or his nominee.
24. Secretary to the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Department of Agriculture), or his nominee.
25. Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines & Metals (Department of Petroleum & Chemicals), or his nominee.
26. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, or his nominee.
27. Joint Secretary (Transport & Communication Division), Planning Commission.
28. Director, Central Water and Power Research Station, Poona.
29. The Director General of Shipping, Bombay.
30. Chief Commissioner, Andaman & Nicobar Islands, or his nominee.
31. Chairman, Bombay Port Trust, Bombay.
32. Chairman, Calcutta Port Commissioners, Calcutta.
33. Chairman, Madras Port Trust, Madras.
34. Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
35. Chairman, Cochin Port Trust, Cochin.
36. Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham (Kutch).
37. Chairman, Mormugao Port Trust, Mormugao (Goa).
38. Chairman, Paradip Port Trust, Paradip (Orissa).
39. Chief Engineer & Administrator, Tuticorin Harbour Project, Tuticorin.
40. Chief Engineer & Administrator, Mangalore Harbour Project, Panambur *via* Mangalore.
41. Captain of Ports, Government of Goa, Daman & Diu, Panaji.

ORDER

Members

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970